वर्ष : 1 अंक : 1 मार्च, 2026 मूल्य : ₹25

RNI : UPHIN/26/A0322

पंचायत वॉयस

पंचायत से परिवर्तन...

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

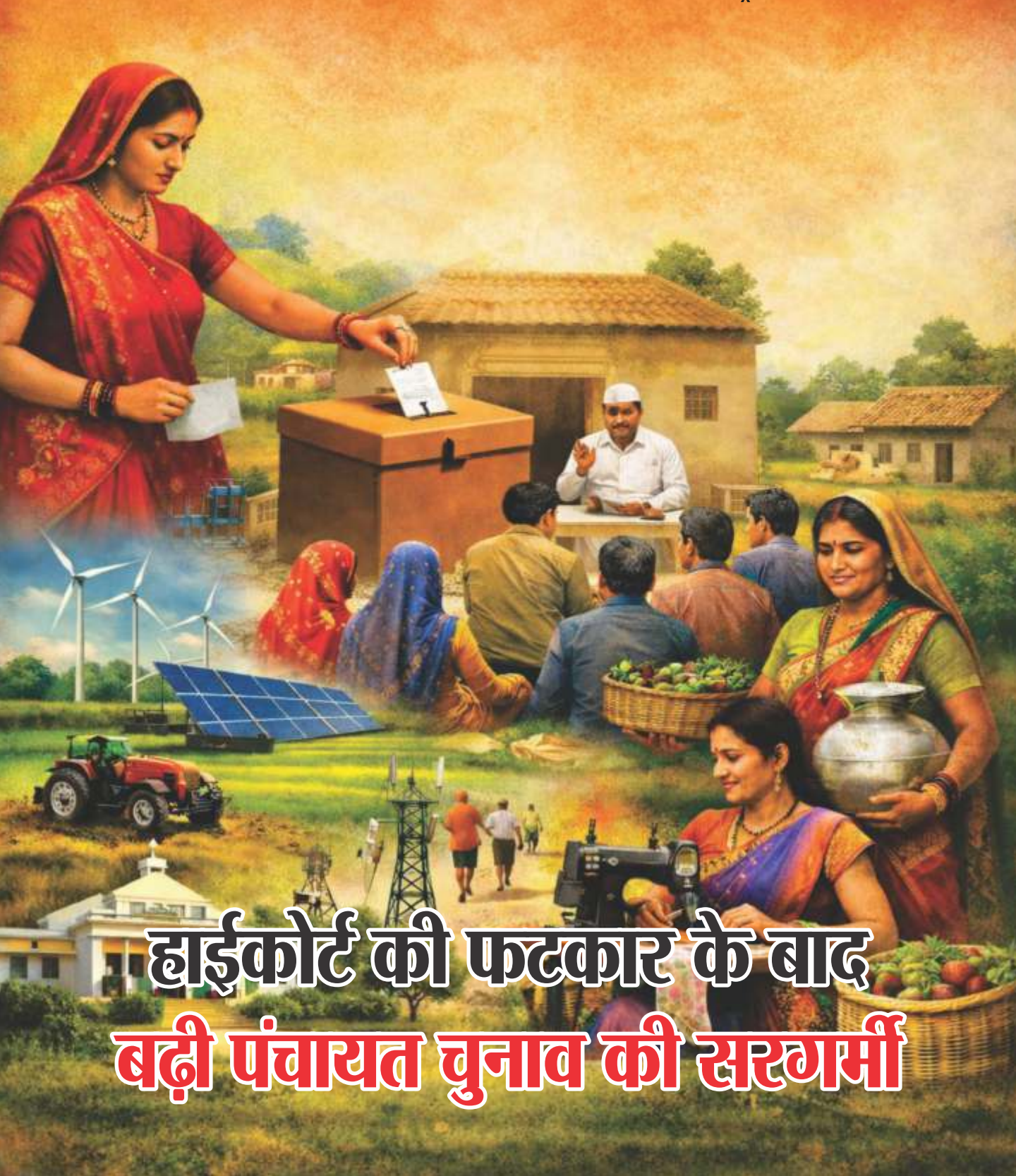

हाईकोर्ट की फटकार के बाद बढ़ी पंचायत चुनाव की सरगर्मी

लखनऊ देवा रोड पर फ्री होल्ड आवासीय प्लाट

प्लाट | विला | आवासीय | व्यावसायिक

AMENITIES

- Sai Temple
- Commercial Shops
- Club & Sports Zone
- Gym & Yoga Centre
- Park with jogging track
- Play Area for Kids
- Open Drainage System
- Wide Damar Road
- 24x7 Security System
- Electricity Poles

Location Map

Location Advantage

- 15 Minutes drive from Gomti Nagar Railway Station
- 15 Minutes drive from Polytechnique Chauraha
- 12 Minutes drive from New High Court
- 10 Minutes drive from Matiyari Chauraha
- 05 Minutes drive from Proposed Metro Station
- 02 Minutes drive from Shri Ram Swarup University

Just 100 meter from Kisan path

पहले बाउन्डरी
फिर रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज

SHREE GULAB ASHIYANA INFRATECH PVT. LTD.

Head Office : Gulab Ashiyana Phase 2, Ganeshpur Rahmanpur, Deva Road, Lucknow

7897711111, 8853801111, 8853901111 gulabashiyana@gmail.com

इस अंक में

पंचायत से परिवर्तन
पंचायत वॉयस
राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
वर्ष 01 अंक 01 मार्च-2026 (प्रवेशांक)

सलाहकार संपादक
रामेंद्र सिन्हा
(वरिष्ठ पत्रकार)
रविकांत प्रसाद
(वरिष्ठ पत्रकार)
संपादक
राजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रबंधक
नीलम श्रीवास्तव
विज्ञापन प्रबंधक
आर्दश श्रीवास्तव

राज्य ब्यूरो
बिहार : प्रभात कुमार
झारखंड : कौस्तुभ कुमार मलयज
जम्मू-कश्मीर : राज लक्ष्मी

ब्यूरों
गोरखपुर : निखिल पाण्डेय
देवरिया : गणेश धर द्विवेदी
सुल्तानपुर : नम्रता श्रीवास्तव

प्रधान कार्यालय
24/112, दुर्गा मंदिर के पीछे, राघव नगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001

स्वामी, प्रकाशक राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा 39, खसरा नं.–166, नियर यूनिटी सिटी, कल्याणपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226022 से प्रकाशित, संपादक राजेश कुमार श्रीवास्तव तथा मुद्रक नीलम श्रीवास्तव द्वारा 41/381, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001 से मुद्रित।

संपादक
राजेश कुमार श्रीवास्तव
संपर्क नं. : 9876917688

panchayatvoice.up@gmail.com
www.panchayatvoice.in

समाचारों का चयन PRP ACT 2023 के अनुसार किया गया है।

सभी विवाद लखनऊ न्यायालय के अंतर्गत मान्य होंगे।

सभी पद अवैतनिक हैं

RNI : UPHIN/26/A0322

शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का वनवास खत्म!

हाईकोर्ट की फटकार के बाद बढ़ी पंचायत चुनाव की सरगर्मी

गोरखपुर : प्रगति का उभरता मॉडल

ममता का किला बनाम भाजपा का मिशन

संपादकीय

संपादक की कलम से

संपादकीय

गांव के विकास से ही राष्ट्र का भविष्य

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कथन है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। यदि देश का सर्वांगीण विकास करना है तो गांवों की स्थिति में सुधार करना अनिवार्य है, तभी राष्ट्र का उत्थान किया जा सकता है। देखा जाए तो वास्तविक रूप से गांवों का कायाकल्प 73वें संविधान संशोधन 1993 से प्रारंभ हुआ। पंचायतों के विकास को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच भी गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास "ग्राम स्वराज" पर आधारित थी। उनका मानना था कि जब पंचायतें सशक्त होंगी, तभी सही मायने में लोकतंत्र मजबूत होगा।

अटल जी तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 16 मई 1996 को (13 दिनों के लिए), दूसरी बार 19 मार्च 1998 को (13 महीने के लिए) और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, यह 2004 तक का पूर्ण कार्यकाल रहा। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा से "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के माध्यम से गांवों को मुख्यधारा से जोड़ा। "अटल भूजल योजना" जैसे आयामों से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दूरदर्शी सोच रखी, ताकि गांव का धन गांव के विकास में लगे।

कहने के लिए तो पंचायती राज भारत में जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, माना जाता है कि यह शासन प्रणाली जनता के सबसे करीब होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद), पंचायत समिति (ब्लॉक परिषद) और जिला परिषद (जिला परिषद) ये तीन स्तर हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था की मूल ईकाई हैं, जहां से व्यवस्था का संचालन होता है। इसका उद्देश्य गांव, ब्लॉक और जिले का विकास करना है। प्रशासन को इसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

आज ग्राम पंचायतों में प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था है। खेत-खलिहान जाने के लिए गांव सड़क मार्ग से जुड़ गए, गांवों के मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया, लेकिन सही मायने में ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास अभी भी बाकी है, यह पूरा हुए बगैर, "ग्राम स्वराज" का सपना अधूरा है। पंचायतों में स्वरोजगार की घोर कमी है। घरेलू-कुटीर उद्योग बंद हो गए। रोजी-रोटी के जुगाड़ के लिए लोग गांवों को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ लिए। गांव के विकास को भ्रष्टाचार की जड़ों ने जकड़ लिया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जो सर्वविदित हैं। भवन बनते नहीं कि छतें गिर जाती हैं, सड़कें बनतीं नहीं कि टूटने लगती हैं। शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक की व्यवस्था प्रश्न वाचक चिह्न के दायरे में हैं। इन समस्याओं के निराकरण एवं आदर्श गांव की स्थापना के उद्देश्य हेतु हमने "पंचायत वॉयस" राष्ट्रीय मासिक मत्रिका का शुभारंभ किया है।

"पंचायत वॉयस" का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने पाठकों को सही व सटीक जानकारी देना है, जिससे वे लोकतंत्र की मजबूती में एक सचेत और सक्षम नागरिक की भूमिका का निर्वहन कर सकें। हमारी प्राथमिक सोच "तथ्य ही सत्य है" की है, इससे हम समझौता नहीं करते। यह पत्रिका देश के ग्रामीण और शहरी जीवन में व्याप्त चुनौतियों के निराकरण एवं बेहतरी की संभावनाओं पर आधारित जन सरोकार से जुड़ी है। हमारा मूलभूत उद्देश्य "पंचायत से परिवर्तन" का है, जहां गांव की पंचायत से लेकर देश की पंचायत तक की बात होगी।

प्रवेशांक के रूप में यात्रा की शुरुआत में यह पहला कदम है। आगे की राह लंबी है और इसमें चुनौतियां भी होंगी, लेकिन हम पाठकों से वादा और इस बात की घोषणा करते हैं कि हम जटिल सवालों से नहीं बचेंगे। अपनी इस यात्रा में हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे। जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। हमारा जोर समाज में पत्रकारिता को मजबूती के साथ खड़ा करने पर है। हमारी कोशिश है कि हिन्दी पत्रकारिता में "तथ्य ही सत्य है" का मूल्य स्थापित हो।■

सादर।

संपादक
राजेश कुमार श्रीवास्तव

Panchayat Voice

संदेश

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री
कृषि, कृषि शिक्षा एवं
कृषि अनुसंधान विभाग
उत्तर प्रदेश

कार्यालय दूरभाष/फैक्स : 2232047
सी.एच. : 2213256
कार्यालय कक्ष संख्या 66-70
मुख्य भवन

सं.175/मं., मंत्री/कृ.वि.कृ.अनु./2026
दिनांक 17/2/2026

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि "पंचायत वॉयस" राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से किया जा रहा है। पंचायत वॉयस का पूर्वांचल समाज और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है। यह माध्यम ग्रामीण लोगों को उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करेगी और उन्हें एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह पत्रिका ग्राम सभाओं से संबंधित जानकारी, पारदर्शिता और तकनीकी (डिजिटल) के सही उपयोग से ही हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य का सपना पूरा कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक जागरूक, सशक्त और शिक्षित पंचायत का निर्माण करेंगे, साथ ही पत्रिका में हम सामाजिक, राजनीतिक, ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा, कला, साहित्य, व्यापार व खेल सहित अन्य विषयों का समावेश होगा जिससे पाठकों एवं अपने जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करेगी।

मेरी ओर से इस "पंचायत वॉयस" राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

(सूर्य प्रताप शाही)

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी,
पता–59/166, यूनिटी सिटी कल्याणपुर,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226022
मो0नं0 9876917688

विजय लक्ष्मी गौतम
राज्य मंत्री
प्राथमिक शिक्षा विभाग एवं
बेसिक शिक्षा विभाग, शासन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मो0–[illegible] बापू भवन, लखनऊ
दूरभाष क्र0 : [illegible]

दिनांक.....

शुभकामना संदेश

मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि **पंचायत वॉयस**, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा **प्रवेशांक अंक** मासिक पत्रिका का प्रकाशन होने जा रहा है।

मुझे खुशी है कि पत्रिका द्वारा मासिक में अपने क्षेत्र के पंचायत के सदस्यों एवं सदस्य का जनहित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संदेश होगा। मुझे उम्मीद है कि मासिक होने से यह मासिक पत्रिका के इस संस्करण में ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी लेखों व समाचारों का समावेश होगा, जिससे सभी को प्रेरणा मिलेगी।

मैं **पंचायत वॉयस** लखनऊ, उ0प्र0 के **प्रवेशांक अंक** मासिक पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं।

(विजय लक्ष्मी गौतम)

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी
राष्ट्रीय संपादक सेंटर,
59/166, यूनिटी सिटी, कल्याणपुर, लखनऊ, उ0प्र0

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद-देवरिया

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

नगरपालिका परिषद गौरा बरहज की तरफ से गौरा बरहज की समस्त जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं सन्देश देती है:-

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

1. नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये रखने में सहयोग करें।
2. किसी भी सार्वजनिक सड़क / गली/पटरी पर अतिक्रमण न करें।
3. 'स्वच्छ भारत मिशन' के अन्तर्गत खुले स्थल पर शौच करना एक सामाजिक अपराध है अतएव खुले स्थल पर शौच न करें एवं नाली में मल इत्यादि न बहाएँ। इसको करने पर आपके विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. नगर के प्रत्येक भवन स्वामी कम से कम दो वृक्ष अवश्य लगाएँ।
5. नगर के प्रत्येक भवन स्वामी से अनुरोध है कि जिनका मकान पालिका में दर्ज नहीं है वे अपना मकान पालिका में दर्ज करा लें।
6. नगर मे लगे पथ-प्रकाश की सुरक्षा करना आपकी जिमेदारी है।
7. "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक अपने मकान में शौचालय अवश्य बनवायें।
8. नगर में पालिथिन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित है, कृपया इसका प्रयोग न करें। नाले- नालियों में पालिथिन से जल प्रवाह रूक जाता है।
9. नगर पालिका अध्यक्ष महोदय द्वारा 10वीं से 12वीं तक छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग का Addmission शिघ्र ही किया जायेगा। Addmission के लिए आप इस नं. 8858319442, 8737983441 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
10. नगर पालिका द्वारा शिकायत प्रकोष्ट की स्थापना किया गया है जिसका हेल्पलाइन नं.-8858319442, 8737983441
11. नगर वासियों से अनुरोध है कि अपने घर से निकलने वाले सुखे कूड़े को अलग एवं गीले कूड़े को अलग करके सफाईकर्मी को उपलब्ध करावें।
12. सभी नगर वासियों एवं मैरेज हाल प्रबन्धन से अनुरोध है कि अपने घर/मैरेज हाल का बचा हुआ भोजन नगर पालिका के कान्हा गौशाला में भेजने का कष्ट करें या इस मोबाइल नम्बर-8299660656 पर सूचित करें।

श्रीमती निरुपमा प्रताप
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
गौरा बरहज,
जनपद-देवरिया

समस्त सभासदगण
नगर पालिका परिषद
गौरा बरहज,
जनपद-देवरिया

श्रीमती श्वेता जायसवाल
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
गौरा बरहज,
जनपद-देवरिया

पत्र संख्या- मंत्री / 2026-नगपालपरि० (2025-26)

सौगात

शिक्षामित्रों-अनुदेशकों का वनवास खत्म!

सीएम योगी की बड़ी घोषणा- मिलेंगे 18000 रुपए मानदेय, 80% हुई वृद्धि

पंचायत वॉयस, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षा मित्रों का 9 साल का वनवास खत्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले ऐतिहासिक घोषणा करते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपए और अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार करने का फैसला किया है। राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन 20 फरवरी को विधानसभा में सीएम योगी ने यह घोषणा की। लंबे इंतजार के बाद शिक्षामित्रों को संजीवनी मिली है। इसके साथ ही, सीएम योगी ने शिक्षामित्रों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा की भी घोषणा की। उत्तर प्रदेश में फिलहाल डेढ़ लाख के करीब शिक्षामित्र संविदा पर काम कर रहे हैं। इनके अलावा प्रदेश में 28 हजार अनुदेशक भी काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्रों का मानदेय योगी सरकार ने 80 परसेंट बढ़ाया है। शिक्षा मित्रों के लिए की गई योगी सरकार की बड़ी घोषणा को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है।

सीएम योगी का विपक्ष पर तंज:

इस बड़ी घोषणा के दौरान सीएम योगी ने मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षामित्र और अनुदेशकों को आप 3,000 रुपये देते थे, हमने 10,000 किए हैं। अब अप्रैल से उन्हें 18,000 रुपए मिलेंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उनको तत्काल हम लोग भुगतान करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

हालांकि शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने इसे लगातार उठाते रहे हैं।

1999 में शुरू हुई थी पहल:

आपको बता दें कि वर्ष 1999 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षामित्रों को रखने की शुरुआत की गई। 2005-06 में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई। लगभग 2009 तक इन्हें बढ़ी संख्या में स्कूलों में पठन-पाठन के लिए तैनात किया गया। बाद में इनको आवश्यक ट्रेनिंग दिलाकर दो चरणों में नियमित किया गया।

2017 में समायोजन हो गया था निरस्त:

प्रदेश में कार्यरत लगभग 1.50 से ज्यादा शिक्षामित्रों को 35-40 हजार रुपये वेतन दिया जाने लगा था। सपा सरकार के आखिरी समय में कुछ शिक्षामित्रों का समायोजन रह गया था। लेकिन पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट से टीईटी पास न होने के कारण 2017 में उनका समायोजन निरस्त कर दिया गया था। तबसे वे 10 हजार रुपये मानदेय पर काम कर रहे थे। इसके बाद से वे लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग और इसके लिए आंदोलन कर रहे थे।

सीएम योगी द्वारा मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बाद शिक्षामित्रों का नौ साल का वनवास प्रदेश सरकार ने खत्म करते हुए मानदेय बढ़ाकर लगभग दोगुना करने की घोषणा की है, जो एक

अप्रैल से लागू होगा। आपको बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने शिक्षकों के साथ शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी

शामिल किया गया है।

सीएम द्वारा सदन में शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर के शिक्षामित्रों व उनके परिवार में खुशी फैली गई। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, महामंत्री सुशील यादव व संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने सीएम योगी की इस घोषणा का स्वागत किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के 1.43 लाख शिक्षामित्र परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। वे और अधिक मनोयोग से शिक्षण कार्य करेंगे। सुशील यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। आर्थिक संकट की वजह से अपने बच्चों की शिक्षा, अपने

माता-पिता का भरण पोषण और घर खर्च चलाने में संतुलन नहीं बना पा रहे थे। बड़ी संख्या में परेशान शिक्षा मित्र और अनुदेशक आत्महत्या तक कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री की इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद शिक्षामित्रों में खुशी का माहौल है। सुशील यादव ने उम्मीद जतायी कि आने वाले समय में सरकार शिक्षा मित्रों के लिए और अधिक बेहतर कार्य करेगी।

अनुदेशकों के परिवार में हर्ष का माहौल:

प्रदेश में 2013-14 में तत्कालीन सपा सरकार ने लगभग 25 हजार अनुदेशकों की तैनाती की थी। इन्हें 7000 रुपये मानदेय पर रखा गया था। इन्हें जूनियर हाईस्कूल में कला, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, खेलकूद आदि विषयों में पढ़ाई व प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया।

इसके बाद 2017 में इनका मानदेय 1400 रुपये बढ़ाया गया। हालांकि बाद में इसे वापस 7000 रुपये कर दिया गया था। भाजपा सरकार ने नवंबर 2021 में इनका मानदेय दो हजार बढ़ाते हुए 9000 रुपये किया। और अब मुख्यमंत्री योगी ने इनका मानदेय 9000 से बढ़ाकर 17000 रुपये करने की घोषणा की है।

शिक्षामित्रों की नियुक्ति, एक नजर...

- 26 मई 1999 को शिक्षामित्र योजना लागू हुई। 1450 रुपये मानदेय।
- 2000-2001 में इनका मानदेय बढ़ाकर 2250 रुपये किया गया।
- अक्तूबर 2005 में मानदेय 2250 रुपये से बढ़कर 2400 हुआ।
- 15 जून 2007 को मानदेय 2400 रुपये से बढ़कर 3000 हुआ।
- 11 जुलाई 2011 को शिक्षामित्रों के दो वर्षीय प्रशिक्षण का आदेश।
- 23 जुलाई 2012 को कैबिनेट ने समायोजन का निर्णय लिया।
- 19 जून 2014 को पहले बैच में 60442 शिक्षामित्रों के समायोजन प्रक्रिया
- 08 अप्रैल 2015 को 77075 शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया
- समायोजन के बाद शिक्षामित्रों का वेतन 35-40 हजार रुपये हुआ।
- 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन निरस्त किया।
- 07 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।
- 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन को निरस्त किया।
- 01 अगस्त 2017 में मानदेय 3500 से बढ़कर 10 हजार रुपये हुआ।
- और अब इन्हें 18 हजार रुपए मिलेंगे मानदेय.■

बजट

बजट-10 लाख युवाओं को रोजगार देगी योगी सरकार

बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपए देगी सरकार

पंचायत वॉयस, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते 10 फरवरी को दसवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने घोषणा की कि यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार संभावित हैं। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बेटियों की शादी के लिए सरकार एक लाख रुपये देगी। यूपी का इस बार के बजट में पिछले बजट की तुलना में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु नए केंद्र बनेंगे:

पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं के कौशल संवर्द्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी।

युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना आवश्यक:

एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

डिजिटल इन्टरप्रन्योरशिप योजना पर कार्य

प्रदेश में डिजिटल इन्टरप्रन्योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि कार्यवाहियों को और अधिक सहज एवं सुगम बनाया जाएगा।

एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना होगी:

- विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी।
- एसडीजी इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गयी है।
- राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया।
- अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है।
- इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है।
- भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयां प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

बजट में महिलाओं के लेकर बड़े ऐलान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट का ऐलान करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करते हुए लगभग 107 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया।

महिलाओं के लिए जॉब प्लेसमेंट केंद्र:

बजट में प्रदेश की महिलाओं के लिए पीपीपी मोड में कौशल संवर्द्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए अलग केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

दुग्ध उत्पादन में महिलाएं:

- महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों का गठन होना था, जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है।

महिला गन्ना किसान:

- महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है.

- सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एण्टी रोमियों स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

वर्किंग वूमेन हॉस्टल:

- सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नये शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है।
- मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है.
- मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।■

राजकीय पक्षी के संरक्षण के लिए विकसित होगा सारस सर्किट

पंचायत वॉयस, लखनऊ

मैनपुरी और इटावा के वेटलैंड क्षेत्र में विकसित होगा सारस सर्किट, सारस संरक्षण के साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा

-जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री

योगी सरकार प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस यानि क्रेन के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट की स्थापना कर रही है। सारस सर्किट का विकास प्रदेश के मैनपुरी और इटावा जिलों के वेटलैंड्स में किया जा रहा है। जिसके तहत मैनपुरी के किर्थुआ, सहस, कुर्रा जरावां, सौज एवं समन के साथ इटावा के सरसई नावर और परौली रामायण वेटलैंड एरिया में सारस सर्किट विकसित किया जा रहा है।

सारस सर्किट में सारस पक्षी के संरक्षण के साथ इको टूरिज्म की गतिविधियों को भी शामिल किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सारस पक्षी और वेटलैंड्स संरक्षण के साथ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह स्थानीय लोगों को आय के अवसर उपलब्ध करवाएगा और सारस पक्षी और वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए भी प्रेरित करेगा। इन परियोजनाओं का विकास ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के माध्यम से प्रदेश का वन विभाग कर रहा है।

दुनिया में सबसे लंबी उड़ान के लिए जाना जाने वाला सारस पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसका आवास और प्रजनन क्षेत्र विशेषतौर पर राज्य के मैनपुरी, इटावा, एटा, अलीगढ़ की वेटलैड्स में है। जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार सारस पक्षी के संरक्षण के लिए सारस सर्किट का विकास कर रही है। जहां प्रदेश का वन विभाग, यूपी ईको टूरिज्म विकास बोर्ड के माध्यम से क्षेत्र के उथले जलाशयों, तालाबों और अन्य वेटलैड्स को संरक्षित कर सारस पक्षी के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही क्षेत्र में ईको टूरिज्म की गतिविधियों को भी विकसित किया जा रहा है।

मैनपुरी और इटावा जिलों के सारस सर्किट में प्रवेश द्वार, व्यू पॉइंट, डेक एवं बोटिंग स्पॉट, बटरफ्लाई गार्डन, सोलर साइट लाइटिंग, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सारस सर्किट में पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना केंद्र, ईको-टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, इंटरैक्टिव साइनेज, फूड कियोस्क और ओडीओपी व स्मृति चिन्ह की दुकानें विकसित की जाएंगी। ये सुविधाएं पर्यटकों को सारस के प्राकृतिक आवास को देखने और समझने का अवसर प्रदान करेंगी। योगी सरकार की यह पहल न केवल सारस क्रेन और अन्य पक्षियों जैसे- ग्रे हेरॉन, ओपन-बिल्ड स्टॉर्क आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि क्षेत्र के वेटलैंड्स के संरक्षण को भी बढ़ावा देगी। यह इन क्षेत्रों में भू-जल स्तर में वृद्धि के साथ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म की गतिविधियों के विकास से स्थानीय समुदाय के लोगों को आय और रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय लोगों और घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में बढ़ोतरी होगी। सारस पक्षी को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर योगी सरकार क्षेत्र की जैव विविधता को संजोने का अनूठा प्रयास कर रही है। ये परियोजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत विकास की अवधारणा को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

कवर स्टोरी

हाईकोर्ट की फटकार के बाद बढ़ी पंचायत चुनाव की सरगर्मी

जुलाई 2026 तक हर हाल में करा लिए जाएंगे पंचायत चुनाव: ओमप्रकाश राजभर

पंचायत वॉयस, लखनऊ

हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता के माहौल पर विराम लग गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी।

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि राज्य में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे। राजभर ने कहा कि साल 2021 में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जुलाई महीने में पूरी हो गई थी। इस बार भी जुलाई तक पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों तैयार हैं।

ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायत चुनाव कराने की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव के लिए जिलों में मतपत्र भी छप गए हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन भी 15 अप्रैल तक हो जाएगा। चुनाव में ओबीसी आरक्षण को तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाना है। जल्द ही ये प्रक्रिया भी पूरी होगी, जिसके बाद आरक्षण प्रक्रिया को फाइनल कर लिया जाएगा।

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय किया जाएगा। फ़िलहाल कोई नई गणना नहीं कराई जाएगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव कार्यक्रम को घोषित कर दिया जाएगा।

राजभर ने कहा कि भले ही ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत

राज्य में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे।

-ओमप्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्री

अध्यक्षों के कार्यकाल अलग-अलग समय पर खत्म हो रहे हैं लेकिन किसी का कार्यकाल जुलाई 2026 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव की समय सीमा को ध्यान में रखकर ही चुनाव कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तय किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी को तैयारी संबंधी निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर कड़ा रवैया अख़्तियार किया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से सवाल किया है कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद क्या 26 मई तक चुनाव कराना संभव है या नहीं। कोर्ट ने इसे लेकर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है।

"किन्हीं कारणों से यदि चुनाव नहीं हो पा रहे हैं तो प्रशासक नियुक्त न किए जाएं। जो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल चुनाव होने तक रखा जाए, ताकि क्षेत्र का विकास कार्य बाधित न हो।"

-गिरीश तिवारी,
अध्यक्ष, जिला परिषद, देवरिया

कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग के गठन को मिलेगी मंजूरी:

ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल जाएगी। आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगा और कोई नई गणना नहीं कराई जाएगी। पूर्व में लागू आरक्षण चक्र को ही जारी रखा जाएगा। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट मिलते ही सीटों का आरक्षण तय कर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने क्या कहा-

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मार्च को सख्त रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव समय सीमा के भीतर क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करा सकेगा या नहीं?

याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन ने कोर्ट को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 243E पंचायतों के अधिकतम पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। यह अवधि उनकी पहली बैठक की तारीख से शुरू होती है और इससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसे में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है।

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12BB के अनुसार, पंचायत चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद जारी की जाती है। यानी चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का अंतिम निर्णय यूपी सरकार के पास है।

समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आरक्षण नीतियों को पारदर्शी तरीके से लागू करने हेतु सरकार सुविधानुसार कदम उठाए। इसमे यदि समय लगता है तो हमारी मांग है की सरकार प्रशासक ना नियुक्त कर जन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ा दें"

-डॉ. अवध किशोर
अखिल भारतीय प्रधान संगठन, जिला उपाध्यक्ष, महराजगंज, उत्तर प्रदेश

"यदि समय पर चुनाव न होने की स्थिति बनती है तो, सरकार प्रशासक नियुक्त न करे। इसकी जगह जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि विकास कार्य अपनी गति से चलता रहे।"

-राजेंद्र सिंह पटेल,
ब्लॉक प्रमुख, सैदाबाद, प्रयागराज

सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले संपन्न कराना अनिवार्य है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च 2026 तय की गई थी, लेकिन 25 तारीख को सुनवाई नहीं हो सकी।

2 मई 2026 को खत्म हो जाएगा कार्यकाल:

ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसी आधार पर पंचायत चुनावों को अप्रैल से जून 2026 के बीच कराने का प्रस्ताव रखा गया है। ■

कवर स्टोरी

यूपी की महिला प्रधानों को मिला राष्ट्रीय सम्मान

"महिला नेतृत्व ग्रामीण विकास की नई शक्ति, यूपी की महिला प्रधान बन रही हैं, प्रेरणा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सशक्त उपस्थिति रही

-ओमप्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्री

पंचायत वॉयस, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की महिला पंचायत प्रतिनिधि आज ग्राम विकास और सुशासन की मजबूत आधारशिला बनकर उभर रही हैं। पंचायतों में महिला नेतृत्व न केवल ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रहा है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जनभागीदारी का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के अंतर्गत निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की महिला प्रधानों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से प्रदेश का मान बढ़ाया। उत्तर प्रदेश से इस सम्मेलन में 135 महिला प्रधानों ने प्रतिभाग कर प्रदेश की सशक्त पंचायत व्यवस्था और महिला नेतृत्व की प्रभावशाली भूमिका को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। यूपी से 10 अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। "बीकन पंचायत (WER)" श्रेणी में उत्तर प्रदेश की प्रियंका तिवारी (ग्राम पंचायत राजपुर, जनपद हाथरस), नीलम देवी (ग्राम पंचायत भरतपुर, जनपद अलीगढ़), मनु यादव (ग्राम पंचायत फौलादपुर, जनपद अमरोहा), पूनम सिंह (ग्राम पंचायत रोरी, जनपद गाजियाबाद) तथा नीलमणि राजे बुंदेला (ग्राम पंचायत छिपाई, जनपद ललितपुर) को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार "चौंपियन ऑफ चेंज" श्रेणी में सुलेखा कुशवाहा (ग्राम पंचायत तिलसड़ा, जनपद कानपुर नगर) तथा मधु चौधरी (ग्राम पंचायत मखदुमपुर, जनपद अमरोहा) को सम्मान प्राप्त हुआ। वहीं "महिला हितैषी ग्राम पंचायत (WFGP)" श्रेणी में रूपाली लोधी (ग्राम पंचायत सींगनखेड़ा, जनपद रामपुर), हेमलता पटेल (ग्राम पंचायत सुजानपुर, जनपद फतेहपुर), कृष्णा गंगवार (ग्राम पंचायत अल्हैया, जनपद बरेली), डॉ. अनामिका सिंह (ग्राम पंचायत पाला, जनपद कन्नौज) तथा माधुरी सिंह (ग्राम पंचायत थावर, जनपद लखनऊ) को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

पंचायती राजमंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ग्रामीण विकास को नई गति दे रही है। उत्तर प्रदेश की महिला प्रधान अपने कार्यों से न केवल गांवों के विकास की मिसाल पेश कर रही हैं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही हैं। उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन करने वाली सभी महिला प्रधानों को बधाई देते हुए कहा कि उनका समर्पण और नेतृत्व गांवों के समग्र विकास को और सशक्त बनाएगा।

निदेशक पंचायती राज विभाग अमित कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन महिला जनप्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने तथा एक-दूसरे से सीखने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इससे पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास को गति देने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।

खेल

ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच
हर विकास खंड में बन रहा ग्रामीण स्टेडियम

गणेश धर द्विवेदी

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उभारने के लिए योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में खेल सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। योगी सरकार प्रदेश के हर विकास खंड में एक ग्रामीण स्टेडियम और आपेन जिम के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। फिलहाल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में करीब 30 खेल स्टेडियम निर्माणाधीन हैं। इन स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल, कम से कम 200 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक तथा विभिन्न आउटडोर खेलों के लिए मैदान विकसित किए जा रहे हैं।

इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में खेल प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि गांव-गांव में खेल संस्कृति विकसित हो और ग्रामीण प्रतिभाएं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करें। यह पहल ग्रामीण युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी प्रतिभा को निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। योगी सरकार का लक्ष्य खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। स्पोर्ट्स कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने की योजना है, जिससे खिलाड़ियों को सुव्यवस्थित ढांचे में उन्नत प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं मिल सकें। सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की जाए। खिलाड़ियों के विकास और खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में प्रभावी रूप से किया जाय। गांवों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन संसाधनों और उचित मंच के अभाव में कई प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पातीं।■

> "प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का यह दूरगामी एवं सराहनीय निर्णय है। इस निर्णय से आने वाले समय में हमारे प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाने में बेहतर मौका मिलेगा।
>
> -भूपेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष, भाजपा, देवरिया

यूपी ने नहीं दी तरजीह तो झारखंड ने संवारा इंडियन रेलवे ने दी अयान को पहचान

हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद देवरिया की माटी में पैदा हुए क्रिकेट खिलाड़ी अमन चौधरी की। जिन्होंने कठिन परिश्रम व लगन के पर इंडियन रेलवे की रणजी ट्रॉफी टीम में लगातार दो सत्र जगह ही नहीं बनाई, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाई। हाल ही में दिल्ली में हुए रणजी ट्रॉफी लीग मैच में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के खिलाफ खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

देवरिया सदर क्षेत्र के मलकौली गांव निवासी स्व. ब्रजभूषण की पांच संतानों में सबसे छोटे अयान को बचपन से ही खेलकूद में खासी रुची रही। शुरुआती दौर में गांव की गलियों खेलते-खेलते वे वर्ष 2008 में रवींद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट की बारिकी सिखने पहुंचे जहां अयान की मुलाकात स्थानीय कोच नीरज वाजपेई से हुई। फिर क्या था गुरु शिष्य के संगम के बीच गुरु ने अयान की प्रतिभा को भांपते हुए लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी की दीक्षा देनी शुरू कर दी। कठिन परिश्रम के बल पर युवा आयान ने लेफ्ट आर्य फिरकी गेंदबाजी के रुप में अपनी एक अलग पहचान बधाई। हौसलों से लवरेज इस प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी को अपने यहां यानी यूपी में कोई तरजीह नहीं मिली तो वह झारखंड की तरफ निकल पड़ा।

झारखंड में बेहतरीन प्रर्दशन के दम पर पहले अंडर 19 में फिर अंडर 23 में जगह बनाई। बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए मध्य रेलवे भोपाल ने बुकिंग क्लर्क की नौकरी दे दी। जिसके बाद से वह रेलवे से खेलने लगे।

रेलवे की अंडर 25 टीम से वर्ष 2023-24 में रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला था। उस दौरान कर्नाटक के खिलाफ शानदार लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके। सत्र 2024-25 में दिल्ली की टीम से मैच हुआ। इस बार विराट कोहली व टीम इंडिया के लिए खेल चुके मीडियम पेसर नवदीप सैनी के खिलाफ खेलते हुए सराहनीय प्रदर्शन किया। अयान के बेहतरीन प्रदर्शन को देखने के बाद क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अयान के साथ फोटो खिचवा कर हौसला अफजाई किया। स्थानीय कोच नीरज वाजपेई ने कहा की अयान चौधरी मेहनती खिलाड़ी है। कड़ी मेहनत के बल पर अयान वहां तक पहचा है। उन्होंने कहा कि अयान स्थानीय युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है।।■

हकीकत परत दर परत

महिला सशक्तिकरण

विद्युत सखी और लखपति दीदी मॉडल का डंका

रामेन्द्र सिन्हा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि उत्तर प्रदेश तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, जब उसकी ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हों। तद्नुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को केवल एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सशक्तिकरण के केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री के "स्मार्ट विलेज" के विजन ने प्रदेश की पंचायतों के विकास को नई दिशा दी है और इस दिशा में विद्युत सखी और लखपति दीदी मॉडल अब पंचायत प्रशासन और ग्रामीण बैंकिंग की रीढ़ बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 महिलाओं को विद्युत सखी के रूप में तैनात करने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अधिकांश सक्रिय हैं। ये महिलाएं घर-घर जाकर बिजली मीटर की रीडिंग लेती हैं और मोबाइल ऐप से बिल जमा करती हैं। इससे सरकार का राजस्व बढ़ा है और महिलाओं को अच्छा कमीशन मिल रहा है। ये महिलाएं हर महीने लाखों का ट्रांजैक्शन करती हैं और

- वाराणसी की ये लखपति दीदियां अब न केवल अपनी संस्कृति को बचा रही हैं, बल्कि काशी की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.
- विद्युत सखी मॉडल को अब अन्य राज्य भी अपना रहे हैं, क्योंकि इसने बैंकिंग सेवाओं को मील का पत्थर बना दिया हैं.

कमीशन के रूप में ₹4,000 से ₹15,000 तक कमा रही हैं। इससे ग्रामीणों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती और महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

राज्य आजीविका मिशन के तहत लाखों महिलाओं को समूहों से जोड़कर उन्हें सिलाई, मसाला पिसाई, और सोलर पैनल रिपेयरिंग जैसे कामों में लगाया गया है। सरकार इन्हें 'लखपति दीदी' बनाने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों की सफलता की कहानियां और उनके उत्पादों की मार्केटिंग अब एक बड़े बदलाव की गवाह बन रही हैं। योगी सरकार ने इन्हें 'लोकल फॉर वोकल' का मुख्य आधार बनाया है।

सोनभद्र जिले में 'विद्युत सखी' पहल ने ग्रामीण महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है, बल्कि "ऊर्जा की राजधानी" कहे जाने वाले इस जनपद में बिजली बिल वसूली की प्रक्रिया को भी सुलभ कर दिया है। ये महिलाएं घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से बकाया और चालू बिजली बिल वसूलती हैं। साथ ही, वे मीटर रीडर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। एक सखी को लगभग 1,500 मीटर रीडिंग लेने का लक्ष्य दिया जाता है। इस योजना से जुड़ी महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में ₹2,000 तक के बिल पर ₹20 और इससे अधिक के बिल पर 1% कमीशन मिलता है। वहीं, शहरी क्षेत्र में ₹3,000 तक के बिल पर ₹12 और इससे अधिक पर 0.4% कमीशन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कई विद्युत सखियां अब 'लखपति दीदी' की श्रेणी में आ चुकी हैं, जो साल भर में ₹1 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं।

विद्युत विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से चयनित महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और बिल जमा करने के लिए आवश्यक डिजिटल उपकरण (जैसे स्मार्ट डिवाइस और प्रिंटर) दिए जाते हैं।

झांसी स्थित बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में न केवल महिला सशक्तिकरण और श्वेत क्रांति का एक आधुनिक मॉडल बनकर उभरी है, बल्कि कंपनी ने पलायन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योगी सरकार के

विजन के तहत, इस कंपनी ने ग्रामीण महिलाओं को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कर सीधे बाजार से जोड़ा है। कंपनी का वार्षिक कारोबार लगभग ₹574 करोड़ से ₹725 करोड़ तक पहुंच गया है। यह कंपनी लगभग 1,200 से 1,250 गांवों में सक्रिय रूप से दुग्ध संकलन कर रही है और प्रतिदिन लगभग 3.25 लाख किलोग्राम दूध का संकलन किया जा रहा है। बलिनी का प्रभाव बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों (झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर और महोबा) तक फैला हुआ है। वर्तमान में इससे 80,000 से 86,000 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। काम का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खातों में हर 10 दिन में किया जाता है। अब तक करोड़ों रुपये का भुगतान सीधे महिलाओं को किया जा चुका है। बलिनी की पूरी प्रणाली डिजिटल और पारदर्शी है। इस पहल से झांसी और आसपास के जिलों की हजारों महिलाएं 'लखपति दीदी' बनी हैं, जिनकी सालाना आय ₹1 लाख से अधिक है।

वाराणसी (काशी) में योगी सरकार के 'ओडीओपी' और 'स्वयं सहायता समूह' मॉडल ने पारंपरिक हस्तशिल्प और अगरबत्ती उद्योग को एक नई पहचान दी है। यहां की महिलाओं ने धार्मिक आस्था को अर्थव्यवस्था से जोड़कर "वेस्ट टू वेल्थ" (कचरे से कंचन) का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है।

वाराणसी के मंदिरों, विशेषकर काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलने वाले फूलों के कुंतलों कचरे को अब गंगा में प्रवाहित करने के बजाय अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। सेवापुरी और अन्य विकास खंडों की सैकड़ों महिलाएं इन फूलों को इकट्ठा कर, सुखाकर और

पीसकर प्राकृतिक अगरबत्ती तैयार करती हैं। ये अगरबत्तियां पूरी तरह से केमिकल-मुक्त और चारकोल-मुक्त होती हैं। इनकी सुगंध शुद्ध चंदन, गुलाब और मोगरा जैसी होती है।

वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी एक विलुप्त होती कला थी, जिसे योगी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पुनर्जीवित किया है। इस कला को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है, जो इसकी विशिष्टता को प्रमाणित करता है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस कला को सीख रही हैं। वे सोने और चांदी के आभूषणों के साथ-साथ मूर्तियों और उपहार की वस्तुओं पर बारीक गुलाबी रंग की नक्काशी करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों (जैसे G7 और G20) में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी के उत्पाद भेंट किए हैं, जिससे इसकी मांग विदेशों में बढ़ गई है।

वाराणसी के लकड़ी के खिलौने अपनी जीवंत रंगत और मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को लकड़ी की खराद चलाने और उन पर प्राकृतिक लाख के रंग चढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्लास्टिक के खिलौनों के विकल्प के रूप में इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण कारीगरों की आय में 30-40% की वृद्धि हुई है।

वाराणसी की ये "लखपति दीदियां" अब न केवल अपनी संस्कृति को बचा रही हैं, बल्कि काशी की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। विद्युत सखी मॉडल को अब अन्य राज्य भी अपना रहे हैं क्योंकि इसने बैंकिंग सेवाओं को "मील का पत्थर" बना दिया है। यही नहीं, पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के अलावा, अब महिलाएं 'पंचायत सचिवालय' के संचालन और विकास योजनाओं के चयन में निर्णय लेने वाली भूमिका में हैं। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश की पंचायतें सुशासन के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी हैं। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था अब महज एक सरकारी इकाई न रहकर ग्रामीण विकास का इंजन बन गई है।■

राजनीति

एसआईआर नोटिस पाने वाले 2.80 करोड़ मतदाता सूची में होंगे शामिल

पंचायत वॉयस, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान प्रदेश में नोटिस पाने वाले 2.8 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और मतदाताओं को भी सूची में शामिल किए जाने की संभावना है।

एसआईआर के दौरान कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं के लिए नोटिस तैयार किए गए। इनमें से 3.06 करोड़ नोटिस मतदाताओं को दिए जा चुके हैं। जिनमें से 2.8 करोड़ मतदाताओं ने नोटिस के जवाब में जरूरी दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं और इनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होना तय है। हालांकि नोटिस पाने वाले शेष मतदाताओं की सुनवाई अभी बाकी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शनिवार को प्रदेश में हो रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण- 2026 (एसआईआर) के दौरान दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026 तक) में नागरिकों से दावे एवं आपत्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इसी अवधि में गणना चरण में मिलान न कराने वाले मतदाताओं तथा मिलान में तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस एवं सुनवाई चरण (6 जनवरी से 27 मार्च, 2026 तक) में जारी किये गये नोटिस एवं पूर्ण की गई सुनवाई से संबंधित भी जानकारी साझा की।

चुनाव आयोग ने जारी की दावे एवं आपत्तियों की विस्तृत जानकारी

1) 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल मतदाता- 12,55,56,025

पुरुष मतदाताओं की संख्या- 6,88,43,159 (54.83%)

महिला मतदाताओं की संख्या- 5,67,08,747 (45.17%)

तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या- 4,119 (0.01% से कम)

2) नोटिसों की सुनवाई के सम्बन्ध में:

मिलान न कराने वाले मतदाताओं की कुल संख्या- 1.04 करोड़

मिलान में तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं की संख्या- 2.22 करोड

नोटिस जारी किये जाने की प्रथम तिथि- 14 जनवरी, 2026

नोटिस सुनवाई की प्रथम तिथि- 21 जनवरी, 2026

जनरेटेड नोटिसों की कुल सख्या- शत-प्रतिशत

नोटिस वितरण - 93.8%

06 मार्च, 2026 तक सुनवाई- 85.8%

नोटिस सुनवाई केन्द्रों की संख्या- 5,621

मिलान न कराने वाले मतदाताओं की सुनवाई हेतु यह निर्देश जारी किये गये हैं कि मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु सुनवाई प्रक्रिया में मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। जो मतदाता किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके द्वारा अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अगूठे का निशान लगाकर अधिकृत किया जा सकता है।

3) दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदन-

i) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 6- 70,69,810

पुरुषों की संख्या- 34,96,911

महिलाओं की सख्या - 35,72,603

तृतीय लिंग की संख्या - 296

18 से 29 आयु वर्ग की संख्या -47,81,526

हक़ीक़त परत दर परत

दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 6- 86,69,073
पुरुषों की संख्या - 43,06,364
महिलाओं की सख्या -43,62,323
तृतीय लिंग की संख्या -386
18 से 29 आयु वर्ग की संख्या- 57,30,989

ii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 7- 2,68,682
पुरुषों की संख्या- 1,58,027
महिलाओं की संख्या- 1,10645
तृतीय लिंग की सख्या - 10
दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 7- 3,18,140
पुरुषों की संख्या -1,86,362
महिलाओं की संख्या- 1,31,766
तृतीय लिंग की संख्या -12

iii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 8- 16,33,578
पता परिवर्तन हेतु- 1,12,877
प्रविष्टियों में सुधार हेतु -14,88,115
ईपिक प्रतिस्थापन -31,602
दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन-984
दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 8- 22,55,473
पता परिवर्तन हेतु -1,56,313
प्रविष्टियों में सुधार हेतु -20,25,611
ईपिक प्रतिस्थापन- 71,536
दिव्याग मतदाताओं का चिन्हांकन-2,013

विहित प्रक्रिया के बिना कोई विलोपन नहीं:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार, दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से बिना नोटिस दिए एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पारित सकारण आदेश के बिना कोई नाम विलोपित (खारिज) नहीं किया जा सकता।

नवदीप रिणवा ने बताया कि कुल 93.8 प्रतिशत नोटिसों का वितरण हो चुका है, जिनमें से 85.8 प्रतिशत मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकें-
प्रथम बैठक -29 अक्टूबर, 2025
दूसरी बैठक -19 नवम्बर, 2025
तीसरी बैठक - 08 दिसम्बर, 2025
चौथी बैठक- 06 जनवरी, 2026
पाँचवीं बैठक- 27 जनवरी, 2026

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टों की संख्याः-
भारतीय जनता पार्टी-1,61,581
बहुजन समाज पार्टी-1,54,224
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-97,153
आम आदमी पार्टी-6,480
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-315
अपना दल (सोनेलाल) (राज्यीय)-5,493
समाजवादी पार्टी (राज्यीय)- 1,57,631
कुल संख्या- 5,82,877

6) शिकायतों का निस्तारणः

राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतो के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप पर मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आईडी से लॉगइन कर अपनी शिकायतों को दर्ज कर उनको ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है।

शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 अंक तक दिये जाते है। नागरिकों द्वारा माह-फरवरी, 2026 में दी गयी रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रदेश में एनजीएसपी पर दिनाक 27 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 06 मार्च 2026 तक कुल 92,497 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष कुल 91,790 (9924 प्रतिशत) शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। ■

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-सुलतानपुर

विज्ञप्ति सूचना

नवीन शैक्षिक सत्र का प्रारम्भ 01 अप्रैल 2026 से हो रहा है, जिसमें स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में 06 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें निशुल्क ड्रेस हेतु 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं तथा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक भी वितरित की जाती है। साथ ही बच्चों के लिए एक्स्पोजर विजिट, इकोक्लब, खेलकूद जैसी प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके। हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके रहने, खाने सहित अन्य गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता हैं जहां पर उनके सुरक्षित वातावरण में अपने पठन-पाठन का कार्य किया जा सकता हैं। दिव्यांग बच्चे व आउट ऑफ स्कूल बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है जिसके लिए स्पेशल एजुकेटर तैनात है तथा उनकों वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। हमारे परिषदीय विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, बाउंड्रीवाल की व्यवस्था, फर्नीचर, श्याम पट्ट, टाइल्सयुक्त फर्श, स्वच्छ शौचालय (बालक-बालिका-दिव्यांग वर्ग के लिए अलग-अलग) उपलब्ध है। इसी के साथ स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब की स्थापना है और साथ में बच्चों के हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं जिससे उनका प्रखर विकास हेतु मूल्यांकन संभव हो सके।

पत्रांकः-बेसिक /43624

उपेन्द्र गुप्ता
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर

सियासत

नसीमुद्दीन सिद्दिकी का बसपा के बाद कांग्रेस से भी मोहभंग, साइकिल पर हुए सवार

> बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का रिश्ता बहुत गहरा है, नए साथियों के आने से समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी -अखिलेश यादव

बलिराम सिंह, लखनऊ

बसपा सरकार में 'मिनी सीएम' के नाम से चर्चित नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस पार्टी रास नहीं आई। कांग्रेस में आठ साल रहने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दिकी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके अलावा केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार में शामिल अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, पूर्व मंत्री फूलबाबू सहित कई नेताओं ने 16 फरवरी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में बसपा और कांग्रेस, अपना दल (एस) और भाजपा छोड़कर बड़ी संख्या में प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

इन प्रमुख नेताओं ने ली सदस्यता:

सपा में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू बसपा सहित दीना नाथ कुशवाहा पूर्व विधायक देवरिया, अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रतापगढ़ सदर से पूर्व विधायक राजकुमार पाल, डॉ. दानिश खान एआईएमआईएम कन्नौज पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सदस्य विधान परिषद हुस्ना सिद्दीकी, पूनम पाल एवं पहली ड्रोन पायलट इटावा की रंजना पाल अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई।

बहुत गहरा है सपा –बसपा का रिश्ता:

इस अवसर पर अखिलेश यादव ने सपा में शामिल होने वाले सभी नेताओं एवं साथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का रिश्ता बहुत गहरा है। नए साथियों के आने से समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। 2027 में पीडीए की जीत और बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि यह पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है। होली मिलन से पहले यह पीडीए होली मिलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे।

इस मौके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि आज 15718 लोग विभिन्न दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे सभी नेता और कार्यकर्ता अनुशासन के साथ एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है।

कितना असर डालेंगे नसीमुद्दीन सिद्धिकी:

अब सवाल है कि बसपा-कांग्रेस के बाद साइकिल पर सवार होने वाले नसीमुद्दीन सिद्दिकी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना लाभ पहुंचायेंगे। यह सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। चूंकि नसीमुद्दीन सिद्दिकी को बसपा सरकार में मिनी सीएम कहा जाता था। मायावती की सरकार में 2007 से 2012 के दौरान नसीमुद्दीन को नंबर दो माना जाता था।

लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा की करारी हार के बाद नसीमुद्दीन सिद्दिकी ने आरोप लगाया था कि मायावती ने उनसे 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। नसीमुद्दीन ने ऑडियो क्लिप जारी किया था और इसके जरिए मायावती पर गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद बसपा प्रमुख ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उन्हें "टैपिंग ब्लैकमेलर" करार दिया था।

चूंकि सपा के कद्दावर नेता आजम खान के जेल जाने से पैदा हुए राजनीतिक शून्य का विकल्प के तौर पर नसीमुद्दीन को माना जा रहा है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के मित्र रहे आजम खान को प्रदेश का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता था। अखिलेश सरकार में आजम खान के पास 8 मंत्रालय हुआ करते थे।

ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दिकी को आजम खान का विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दिकी को बुंदेलखंड और अवध के मुस्लिम इलाकों में अच्छा खासा असर माना जाता है।

हालांकि कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि नसीमुद्दीन सिद्दिकी की कोई लोकप्रियता नहीं है। उन्होंने 2018 में कांग्रेस की सदस्यता ली। बावजूद इसके 2019 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अमेठी से हार गए। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर महज 2 हो गईं और वोट परसेंट भी घट गया। ऐसे में हम कैसे मान लें कि नसीमुद्दीन सिद्दिकी एक जनाधार वाले नेता हैं।

संविधान बचाने के संघर्ष में नसीमुद्दीन सिद्दिकी को देना था साथ:

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत कहते हैं कि कांग्रेस सभी जाति व धर्म के लोगों का सम्मान करती है। वर्तमान में हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी हर जाति-धर्म के लोगों के हक- अधिकार के लिए निरंतर लड़ रहे हैं। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दिकी जी को इस संघर्ष में साथ देना चाहिए था, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कांग्रेस छोड़कर चले गए। उनके जाने से पार्टी का नुकसान नहीं होगा।

क्या इंडिया गठबंधन में पड़ सकता है खटास ?:

चूंकि वर्तमान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक हैं। कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल होने से इंडिया गठबंधन में खटास आ सकता है। हालांकि इस मामले में सचिन रावत कहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वैचारिकी लगभग एक है। नसीमुद्दीन जी भाजपा में नहीं गए हैं, वह कांग्रेस की विचारधारा वाली पार्टी में गए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में किसी तरह की खटास नहीं आने वाली है।

पूर्व विधायक राजकुमार पाल को सत्ता रास नहीं आई

राजकुमार पाल का सत्ता से क्यों हुआ मोहभंग?

केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार में शामिल 13 विधायकों वाली अपना दल एस के पिछले साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे राजकुमार पाल भी 16 फरवरी को सपा में शामिल हो गए। राजकुमार पाल प्रतापगढ़ सदर से विधायक भी रह चुके हैं। राजकुमार पाल का सपा में शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। इन्हें एक तरह से देखा जा रहा है कि इन्होंने सत्ता छोड़कर विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। राजकुमार पाल प्रतापगढ़ में भाजपा के पदाधिकारी रह चुके हैं। 2019 के उपचुनाव में राजकुमार पाल प्रतापगढ़ सदर से अपना दल एस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए। इनके सपा में आने से प्रतापगढ़ एवं आसपास के जिलों में पाल समाज में सपा सेंध लगा सकती है। हालांकि राजकुमार पाल सपा को अपने समाज का कितना लाभ पहुंचा सकते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा।■

ऐलेना स्नातकोत्तर महाविद्यालय

ऐलेना पी0 जी0 कालेज

बाहरपुर, लहौटा, सेमरी–सुलतानपुर

सम्बद्ध : डॉ.राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ.प्र.)

संचालित पाठ्यक्रम
B.A., B.Sc., M.A.

प्रस्तावित पाठ्यक्रम
B.Com., M.Sc.
B.Ed., B.T.C.

उपलब्ध सुविधाएं

1. छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा।
2. पुस्तकालय एंव वाचनालय की सुविधा।
3. गरीब छात्र/छात्राओं के लिए विशेष सुविधा ।
4. अनुभवी एंव कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षण कार्य ।
5. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति का प्रवेश निःशुल्क ।
6. खेलकूद की उचित व्यवस्था ।

संस्थापक/प्रबन्धक
शिव कुमार सिंह
मो.8178190289

प्रशासक
नीरज सिंह
मो.9559303462

सम्पर्क सूत्रः 9721267501 , 9450784541

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस विशेष

औपचारिकता से आगे नारी सशक्तिकरण की वास्तविक यात्रा

डॉ.अंजना सिंह सेंगर

मार्च का महीना आते ही विश्व स्तर पर नारी के सम्मान और अधिकारों की चर्चा तेज़ हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंचों से भाषण दिए जाते हैं, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते हैं, सोशल मीडिया पर नारी शक्ति की प्रशंसा में कविताओं और शेर-ओ-शायरी की बाढ़ आ जाती है। हर व्यक्ति अपने शब्दों में नारी की महानता का गुणगान करता दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उस एक दिन में ही समाज नारी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर देना चाहता हो।

किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इन औपचारिक अभिव्यक्तियों से नारी की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन आता है? क्या वर्ष के एक दिन नारी का सम्मान कर लेने से सदियों से चली आ रही असमानताओं और पीड़ाओं का समाधान संभव है?

निश्चित ही इसका उत्तर 'नहीं' है।

नारी की समस्या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी यांत्रिक प्रक्रिया में डालकर कुछ ही क्षणों में सुधारा जा सके। यह समस्या इतिहास की गहराइयों में जड़ें जमाए हुए है। इसके पीछे सामाजिक संरचनाएँ, सांस्कृतिक धारणाएँ, आर्थिक विषमताएँ और मानसिक पूर्वाग्रह जुड़े हुए हैं। इसलिए इसका समाधान भी दीर्घकालीन और ईमानदार प्रयासों से ही संभव है।

> **हम नारी सशक्तिकरण को केवल एक दिवस की औपचारिकता तक सीमित न रखें। इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से लागू करें। जब समाज नारी को केवल दया या सहानुभूति का पात्र न मानकर उसके सामर्थ्य और प्रतिभा को स्वीकार करेगा तब वास्तविक परिवर्तन संभव होगा।**

नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल अधिकारों की घोषणा करना नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना है। जब तक नारी को मनुष्य के रूप में उसकी सम्पूर्ण गरिमा और अधिकारों के साथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक सशक्तिकरण का सपना अधूरा ही रहेगा।

बचपन की स्मृति : समाज की कठोर सच्चाई

नारी की स्थिति पर विचार करते हुए बचपन की एक घटना अनायास स्मृति में उभर रही है। यह लगभग सत्तर के दशक की बात है। बुंदेलखंड के ज़िला जालौन के एक छोटे से गाँव में मेरा बचपन बीत रहा था। उस समय न सोशल मीडिया का दिखावा था और न ही आधुनिक जीवन की भागदौड़, परन्तु समाज की अनेक विकृतियाँ तब भी अपने कठोर रूप में मौजूद थीं।

उस वातावरण में लड़का और लड़की के बीच का भेद केवल सामाजिक प्रवृत्ति नहीं था, बल्कि एक कठोर वास्तविकता था। पुत्र जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता था, जबकि पुत्री का जन्म अक्सर दुख और निराशा का कारण बन जाता था। कई बार यह भी सुनने को मिलता कि किसी घर में बेटी जन्मी और थोड़े ही समय में मर भी गई। यदि वह जीवित भी रह जाती तो पूरे परिवार के चेहरे पर उदासी छा जाती। बेटी के जन्म पर लोग संवेदना व्यक्त करने आते मानो कोई बड़ा दुर्भाग्य घटित हो गया हो।

एक छोटी बच्ची के रूप में मेरे लिए यह सब समझ पाना संभव नहीं था, परंतु धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगा कि समाज में बेटी होना स्वयं एक अपराध की तरह माना जाता है। कई बार मैंने अपने घर आने वाले लोगों को मेरे माता-पिता से यह कहते हुए भी सुना कि ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया है जो उन्हें बेटी दे दी।

इन्हीं दिनों गाँव में एक दिन यह खबर फैली कि वहाँ स्थित करणखेड़ा नामक तीर्थ स्थल पर एक यज्ञ हो रहा है, जिसमें तीन कन्याओं की बलि दी जानी है। किसी ने मज़ाक में या शायद डराने के लिए यह बात कह दी कि उनमें से एक मैं भी हो सकती हूँ। मैं लगभग सात–आठ वर्ष की थी। एक

मासूम बच्ची के लिए यह समाचार भयावह था। उस डर के कारण कई दिनों तक मेरा खाना-पीना छूट गया। मैं घर के भीतर ही छिपी रहती, कहीं बाहर निकलने से डरती कि कहीं किसी ने देख लिया तो मुझे पकड़कर बलि न दे दी जाए।

यह घटना चाहे वास्तविक थी या केवल एक अफवाह, पर उसके प्रभाव ने मेरे बाल मन को गहरे तक झकझोर दिया। उस भय से उबरने में मुझे वर्षों लग गए। उस समय न तो किसी ने मेरी आशंका को समझने की कोशिश की और न ही मेरे मन के भय को दूर करने का प्रयास किया। यह अनुभव केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं था, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का प्रतिबिंब था जिसमें कन्या को बोझ समझा जाता था। यह वही मानसिकता है जिसने सदियों तक नारी को उसके अधिकारों से वंचित रखा।

सनातन संस्कृति में नारी का आदर्श स्वरूप:

यदि हम भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को देखें तो उसमें नारी को अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त है। वैदिक वाङ्मय में यह उद्घोष स्पष्ट रूप से मिलता है—

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।"

अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है।

भारतीय परंपरा में नारी को केवल परिवार की सदस्य के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे ज्ञान, शक्ति और सृजन की प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वैदिक काल की गार्गी, मैत्रेयी, अपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय नारी को ज्ञानार्जन और वैचारिक विमर्श में समान अवसर प्राप्त थे।

गार्गी ने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से दार्शनिक प्रश्न पूछे। मैत्रेयी ने आत्मज्ञान की जिज्ञासा व्यक्त करते हुए सांसारिक संपत्ति को अस्वीकार कर दिया। अपाला और घोषा ने ऋग्वेद में सूक्तों की रचना की।

ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संस्कृति की मूल चेतना में नारी को समान भागीदारी प्राप्त थी। वह केवल परिवार की संरक्षिका नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की निर्माणकर्ता भी थी।

रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी नारी के अनेक प्रेरणादायक रूप दिखाई देते हैं। सीता त्याग और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं, द्रौपदी साहस और स्वाभिमान की प्रतीक हैं, सावित्री दृढ़ निश्चय और निष्ठा की मिसाल हैं।

इन चरित्रों ने भारतीय मानस को यह सिखाया कि नारी केवल कोमलता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें अदम्य शक्ति और संकल्प भी निहित है।

मध्यकालीन परिस्थितियाँ : नारी अस्मिता पर संकट:

इतिहास के प्रवाह में अनेक ऐसे कालखंड आए जब समाज की परिस्थितियों ने नारी की स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया। विशेष रूप से मध्यकालीन दौर में राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी आक्रमणों और सामाजिक रूढ़ियों ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया।

इतिहासकारों के अनुसार हर्षवर्धन के पश्चात भारत में हूणों, शक, कुषाणों और अन्य आक्रांताओं के आगमन ने सामाजिक जीवन में असुरक्षा की भावना को बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप स्त्रियों को घर की चारदीवारी में सीमित करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती जैसी कुप्रथाएँ इसी वातावरण में प्रचलित हुई।

इस काल में नारी अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुज़री। कई बार उसे युद्ध और सत्ता संघर्ष की वस्तु बना दिया गया। राजसत्ताओं के हस्तांतरण में स्त्रियों का क्रय-विक्रय भी हुआ। समाज की संकीर्ण धारणाओं ने उसे शिक्षा और स्वतंत्रता से दूर कर दिया।

फिर भी यह उल्लेखनीय है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी नारी ने समाज और संस्कृति

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस विशेष

की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीरा बाई ने भक्ति के माध्यम से सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने युद्धभूमि में अद्भुत साहस का परिचय दिया।

इस प्रकार नारी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा और समाज को नई दिशा दी।

आधुनिक युग : संघर्ष से उपलब्धियों तक:

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और सती प्रथा के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय स्त्रियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली और दुर्गा भाभी जैसी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने स्त्रियों को समान अधिकार प्रदान किए। शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और विज्ञान सहित लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी।

आज की भारतीय नारी ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विज्ञान में कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रचा। खेलों में पी.टी. उषा, कर्णम मल्लेश्वरी और सानिया मिर्जा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। सेना में शिवांगी सिंह जैसी महिलाएँ आधुनिक युद्धक विमानों का संचालन कर रही हैं।

इन उपलब्धियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि अवसर और संसाधन उपलब्ध हों तो नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है।

फिर भी अधूरी है।

इतनी उपलब्धियों के बावजूद यह कहना कठिन है कि नारी पूरी तरह सशक्त हो चुकी है। आज भी समाज में अनेक समस्याएँ मौजूद हैं—लिंग भेद, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कार्यस्थलों पर असमान वेतन और यौन उत्पीड़न जैसी चुनौतियाँ अभी भी व्यापक रूप से दिखाई देती हैं।

इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म लेकिन गंभीर समस्या समाज की मानसिकता से जुड़ी है। कई बार नारी

की सफलता को स्वीकार करने में समाज संकोच करता है। उसके आत्मनिर्भर बनने को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

इसलिए नारी सशक्तिकरण की वास्तविक चुनौती केवल कानून बनाने में नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने में है।

सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ :

नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल अधिकारों की प्राप्ति नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है - नारी को अपनी क्षमता और संभावनाओं को विकसित करने का अवसर मिलना।

इसके लिए आवश्यक है कि

•शिक्षा का प्रसार हो क्योंकि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता का आधार है।

•. आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, जिससे नारी अपने निर्णय स्वयं ले सके।

• सामाजिक सम्मान मिले, जिससे उसकी प्रतिभा को उचित पहचान मिल सके।

• सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो, जहाँ वह बिना भय के जीवन जी सके।

जब ये सभी तत्व मिलकर कार्य करेंगे तभी नारी सशक्तिकरण का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

निष्कर्षत: समानता और सम्मान की ओर नारी की यात्रा केवल पीड़ा और संघर्ष की कहानी नहीं है बल्कि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की भी गाथा है। सदियों की कठिनाइयों के बावजूद उसने समाज, संस्कृति और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम नारी सशक्तिकरण को केवल एक दिवस की औपचारिकता तक सीमित न रखें। इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से लागू करें। जब समाज नारी को केवल दया या सहानुभूति का पात्र न मानकर उसके सामर्थ्य और प्रतिभा को स्वीकार करेगा तब वास्तविक परिवर्तन संभव होगा।

नारी केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति की प्रेरक शक्ति है। यदि उसे समान अवसर और सम्मान मिले तो वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकती है।

इसलिए नारी सशक्तिकरण का अर्थ है ..

मानवता की आधी शक्ति को उसके पूर्ण अधिकारों के साथ स्वीकार करना... और जब ऐसा होगा, तभी यह विश्व वास्तव में संतुलित, समृद्ध और मानवीय बन सकेगा।■

यूपी में स्थापित हो रही है इंटरनेशनल आलू केंद्र लीमा की शाखा

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का निर्देश-आलू भंडारण के लिए जा रहे किसानों के वाहनों का चालान न किया जाए

पंचायत वॉयस, आगरा

प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने आगरा में आयोजित आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी।

आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में आगरा, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद और कन्नौज सहित विभिन्न जनपदों के आलू उत्पादक किसानों, निर्यातकों, शीतगृह स्वामियों, मंडी परिषद तथा उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आलू की बेहतर उपज को देखते हुए सरकार किसानों को घाटा न उठाना पड़े इसके लिए विपणन और निर्यात की व्यवस्था को मजबूत कर रही है।

उद्यान मंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा (पेरू) की साउथ एशिया शाखा आगरा के सींगना में स्थापित की जा रही है। इससे प्रदेश के किसानों को उत्पादन, भंडारण, विपणन और निर्यात के क्षेत्र में नई संभावनाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में आलू उत्पादन में

> अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा (पेरू) की साउथ एशिया शाखा आगरा के सींगना में स्थापित की जा रही है। चीन के बाद एशिया में इस केंद्र की स्थापना आगरा को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाएगी और आलू बीज अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति लाएगी।

पहले स्थान पर है और देश के कुल आलू उत्पादन में प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आगरा मंडल भी आलू उत्पादन

और भंडारण का प्रमुख केंद्र है, जहां लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 67 लाख मीट्रिक टन से अधिक आलू का उत्पादन होता है तथा लगभग 604 शीतगृह संचालित हैं।

मंत्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष बेहतर उत्पादन को देखते हुए सरकार आलू के विपणन और खपत बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा सरकार के माध्यम से लगभग 15 लाख मीट्रिक टन आलू की खपत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आलू मूल्य स्थिरीकरण के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार से 100 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आलू खरीद और मूल्य स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हाल ही में किसानों द्वारा भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर ले जाए जा रहे आलू के वाहनों के चालान की समस्या पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि भंडारण के लिए ले जाए जा रहे किसानों के वाहनों का चालान न किया जाए।

उन्होंने शीतगृह संचालकों, किसानों और उद्यमियों से आगरा क्षेत्र में आलू आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है तथा किसानों को बेहतर तकनीक और उन्नत किस्मों के विकास के लिए प्रदेश में 125 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं।

सम्मेलन के उपरांत मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सींगना में स्थापित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की साइट का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। ■

खेती-किसानी

सरकार ने बीज उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य और कृषि विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार ने लगभग 31.43 करोड़ रुपये की आवंटित की धनराशि

कृषि स्वावलंबन और शोध कार्यों के सुदृढ़ीकरण से प्रदेश के किसानों का होगा सर्वांगीण उत्थानः सूर्य प्रताप शाही

हक़ीक़त परत दर परत

"राज्य सरकार किसानों के सर्वांगीण उत्थान और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीज स्वावलंबन और मृदा स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के सुदृढ़ीकरण से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था भी आत्मनिर्भर बनेगी। आवंटित धनराशि से कृषि शोध और विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

"सूर्य प्रताप शाही" कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश

पंचायत वॉयस, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और कृषकों की समृद्धि के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कुल 3142.92 लाख रुपये (लगभग 31.43 करोड़ रुपये) की वित्तीय स्वीकृतियां दे दी हैं। यह धनराशि बीज स्वावलंबन, मृदा परीक्षण, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और कृषि विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण जैसी विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं हेतु आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा प्राप्त होने की उम्मीद है।

जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुसार, बीज स्वावलंबन नीति के अंतर्गत खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के बीजों की लागत व प्रासंगिक व्यय हेतु 10.00 करोड़ रुपये (1000.00 लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम हेतु 12.26 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन एवं एरियर के भुगतान हेतु 8.79 करोड़ रुपये (879.03 लाख) की व्यवस्था की गई है। वित्तीय स्वीकृतियों के अगले चरण में, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन प्रोग्राम (अनुसूचित जातियों के लिए) के अंतर्गत 6.20 करोड़ रुपये (620.33 लाख) जारी किए गए हैं।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत संचालित इटावा स्थित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कार्मिकों के वेतन-भत्तों हेतु 3.47 करोड़ रुपये (347.00 लाख) तथा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (सोलर फेंसिंग) के अंतर्गत विज्ञापन एवं अन्य व्यय हेतु 3.00 करोड़ रुपये (300.00 लाख) की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम हेतु 1.69 करोड़ रुपये, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित योजनाओं हेतु 1.75 करोड़ रुपये, कृषि विश्वविद्यालयों के बकाया विद्युत देयों हेतु 75.00 लाख रुपये, ई-ऑफिस व्यवस्था हेतु 10.00 लाख रुपये, जनजाति क्षेत्रों में क्रॉप डायवर्सिफिकेशन हेतु 10.00 लाख रुपये तथा इसी कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जातियों हेतु 7.83 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।■

बिहार का अगला सम्राट कौन...?

क्या बिहार की सत्ता स्थानातंरण में नीतीश की मर्जी चलेगी...?

प्रभात कुमार

बिहार चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती है, यहां का अगला सम्राट कौन होगा...?, यह सवाल बिहार की जनता के जेहन में तैर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित होने बाद यह सवाल और गहरा हो गया है। गांव-गली चौराहे से लेकर राजनीतिक गलियारे तक में सिर्फ एक चर्चा आबो-हवा में चल रही है कि अखिरकार किसके सिर पर बिहार का ताज सजेगा...?, वह कौन सी शख्सियत होगी, जो नीतिश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में नीतीश कुमार की जगह लेगा...?, यह सवाल भी घूम रहा है कि क्या बिहार की सत्ता स्थानातंरण में नीतीश की मर्जी चलेगी...?, या भाजपा हाईकमान तय करेगा। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि भाजपा से गठजोड़ के बाद खुले तौर पर नीतीश कुमार बिहार में समय-समय पर जो संकेत देते रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, या फिर कुछ और...।

वैसे, तमाम कयासों, अटकलों और संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का जो बयान सामने आया, उस बयान ने सभी अटकलों और कयासों पर विराम लगा दिया। उनका बयान आया कि मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है और यह भी तय नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा।

चर्चा है कि बिहार की सियासत को लेकर कहीं हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली से तो नहीं खेला जा रहा है। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इसकी पटकथा देश के गृहमंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के सीमांचल दौरे के दौरान ही लिख दी गई थी। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया में प्रवास किया था। इस प्रवास को लेकर जो बातें सामने आई, उसके मुताबिक घुसपैठियों का मामला और एक नए राज्य के गठन की चर्चा की थी। लेकिन उनके वापस लौटते ही, बिहार में नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया। इससे यह तो साफ हो गया कि उनके आगमन का असल मकसद कुछ और ही था। एक तरफ जब पूरा राज्य होली खुमार में डूबा था, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन नीतीश चल गया और यह अभियान अभी जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं और 10 अप्रैल तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्हें शपथ ग्रहण करना है।

वैसे, बिहार में होली से एक-दो दिन पहले से जिस नई राजनीति की शुरुआत हुई , उससे पूरा बिहार हैरत में है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले वाली सूचना के बाद बिहार से जो लोगों की प्रतिक्रिया आई, वह सबके सामने है। सड़कों पर नारे लगे और फिर होली के दूसरे दिन पूरे बिहार ने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम विरोध और नाराजगी के बावजूद राज्यसभा के लिए पर्चा भरा।

नई राजनीति की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की असहमति की भी बात सामने आई। फिर आनन-फानन में इस फैसले पर निशांत की सहमति का बयान भी जारी हो गया। फिर निशांत के जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने की बात सामने आयी। फिर बिल्कुल घोषणा और तय समय पर यह भी प्रक्रिया पूरी हो गई।

सवाल यह भी है बिहार की बदली हुई सियासत के बीच देश के पांच अलग-अलग राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं और रिजल्ट मई में निर्धारित है। ऐसे में भाजपा हाई कमान बिहार का सम्राट तय करने का कोई रिस्क उठाएगा। अब देखना है कि भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को कब तक बनाए रखती है और कब चाणक्य का आदेश आता है कि अब आप इस्तीफा दें।

दरअसल, पर्दे के पीछे इस बात पर मंथन चल रहा है कि किस चेहरे को सामने लाया जाए, जिसका फायदा पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में मिले और देश को भी ऐसा संदेश जाए, जिस पर विपक्ष उंगली न उठा सके। आलाकमान की नजर इस बात पर भी है कि मुख्यमंत्री का पद संभालने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग का हो और उसकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो। उद्देश्य साफ है, नीतीश की भरपाई और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाना।■

साभार : कीर्ति

गोरखपुर : प्रगति का उभरता मॉडल

निखिल पाण्डेय

19 मार्च 2017 का दिन गोरखपुर शहर के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाला था। गोरक्षनाथ मठ के महंत एवं लगातार पांच बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में एक तरफ शपथ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर के विकास की पटकथा लिखी जा रही थी, जिसके नायक वे स्वयं थे।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में राप्ती और रोहिणी नदियों के संगम पर 3483.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसी संत गोरखनाथ की तपोभूमि अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। विश्व विख्यात गीता प्रेस, नाथ सिद्ध परंपरा का केंद्र और टेराकोटा कला गोरखपुर की पहचान है। पूर्वांचल राज्य की प्रस्तावित राजधानी एवं पड़ोस में नेपाल जैसे देश के नजदीक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बावजूद यह लंबे समय से उपेक्षित रहा।

यद्यपि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं 'आधुनिक गोरखपुर के वास्तुकार' के नाम से प्रसिद्ध 'वीर बहादुर सिंह' ने अपने कार्यकाल के दौरान ही इसे 'बी श्रेणी' के नगर निगम का दर्जा दिलाने के साथ-साथ रामगढ़ ताल परियोजना, महिला आईटीआई, स्पोर्ट्स कॉलेज, नक्षत्रशाला और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की शुरुआत कर बुनियादी रूपरेखा तैयार कर दी थी। वीर बहादुर सिंह को गोरखपुर का विकास पुरुष कहा जाता था, लेकिन उनके निधन के बाद मानो इसके विकास को दीर्घकालीन ब्रेक लग गया।

लोग इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि आखिर क्यों केंद्र और राज्य में कई प्रभावशाली और कद्दावर नेता, मंत्री होने के बावजूद यह दुर्दशा झेलता रहा। बाढ़ की विभीषिका, इंसेफ़लाइटिस की त्रासदी, खराब और गुणवत्ताहीन आधारभूत संरचना, टूटी-फूटी गड्ढा युक्त सड़के, ख़राब ड्रेनेज सिस्टम, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा की कमियों को झेलने के लिए मजबूर रहा।

शहर के कुछ वरिष्ठ नागरिकों से जब इस पर बात की गई तो लगभग सभी ने इसकी बदहाली के पीछे 90 के दशक से 2017 तक शहर पर माफिया,राजनीति औऱ प्रशासन के गठजोड़ से पनपे अपराध और भ्रष्टाचार को प्रमुख कारण बताया, जिसका सीधा प्रभाव शहर के विकास पर पड़ा।

एक समय ऐसा था जब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गोरखपुर को उत्तर प्रदेश में अपराध की राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। एक ऐसा माहौल बना कि बड़े निवेशक गोरखपुर में निवेश करने से डरने लगे और शहर के व्यवसायी शहर छोड़कर जाने लगे थे। इसका सीधा प्रभाव इस क्षेत्र के उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा। इन सब के कारण गोरखपुर के विकास को जो ब्रेक लगा वह काफी लंबे समय तक नगरवासियों को कष्ट देता रहा।

दशकों तक हत्या, लूट, अपहरण, भ्रष्टाचार औऱ अपराध का दंश झेलने वाले इस क्षेत्र ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बदलाव महसूस किया है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गोरखपुर की काया पलट गई और आज गोरखपुर का चौमुखी विकास हो रहा है।

निवेशकों के लिए हॉटस्पॉट बना गोरखपुर

योगी आदित्यनाथ के भय-मुक्त प्रदेश का नारा और अपराध के प्रति जीरो टोलेरेंस की नीति ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सीएम सिटी के नाम

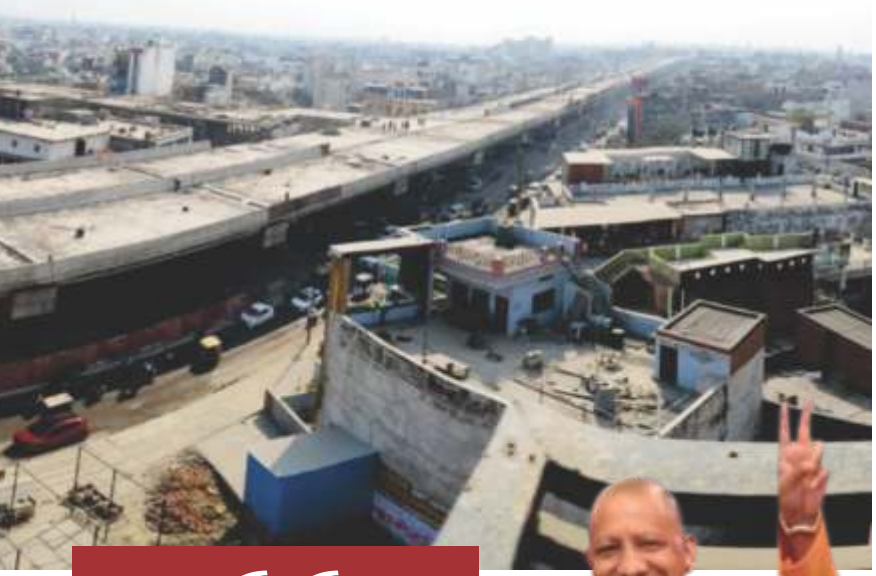

"गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा महानगर में नई अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग और हमारे रचनात्मक कौशल की चर्चा दुनिया में हो रही है। नगर निगम के सभी अंग एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। सभी का इसमें योगदान है। वेस्ट टू वेल्थ नीति पर चलते हुए ग्रीन चारकोल बनाने का काम हुआ, ताकि वातावरण को नुकसान ना हो और इको फ्रेंडली तरीके से निर्माण किया जायेस हाल ही में हमने फ्राइटोरेडिएशन तकनीक का प्रयोग करके किफायती तरीके से जल उपचार कर स्वच्छ जल बनाने में सफलता प्राप्त की है यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसके लिए नगर निगम को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा-ग्लोबल वाटर टेक सम्मान 2025-प्राप्त हुआ। इसका प्रेजेंटेशन जर्मनी में भी किया गया और जर्मनी की टीम इसे सीखने के लिए गोरखपुर आने वाली है। यह हमारी उपलब्धि है। स्वच्छता की रैंकिंग में गोरखपुर 74वें स्थान से आज चौथे स्थान पर आ चुका है, इसके लिए नगर निगम के साथ-साथ गोरखपुर की सम्मानित जनता की जागरूकता की सराहना की जानी चाहिए

-डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव
महापौर, गोरखपुर

से प्रसिद्ध गोरखपुर की ओर निवेशकों का ध्यान आकृष्ट किया। इसका परिणाम है कि जिस गोरखपुर में 2012 से 2017 के बीच निवेश की राशि लगभग 29 करोड़ थी, वह आज 2017 से 2025 के बीच 11618.75 करोड़ पहुंच गई। लगभग 320 औद्योगिक इकाइयों में हुआ यह निवेश शहर में 40 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए

"दशकों की उपेक्षा झेल रहे गोरखपुर ने 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गति पकड़ी है उसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण का योगदान अमूल्य है। जीडीए ने सभी वर्गों के हित को देखते हुए तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने में प्रतिबद्धता से कार्य किया है इसका परिणाम अब दिख रहा है। आवास, पुल, सड़क, पार्क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता सभी क्षेत्रों पर जिस तरह सभी संस्थाएं एवं संगठन काम कर रहे हैं उससे आने वाले 5 -6 वर्षों में गोरखपुर देश के अग्रणी शहरों में शामिल होगा

-दुर्गेश बजाज
सदस्य, गोरखपुर
विकास प्राधिकरण

अवसरों का निर्माण कर चुका है। इन आठ वर्षों में गोरखपुर की जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2018-19 में 19221.83 करोड़ जीडीपी के साथ जो गोरखपुर 15 जिलों में भी शामिल नहीं था, वह आज 47169.76 करोड़ की जीडीपी के साथ 9वें नंबर पर है। जहां, बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, वहीं बड़ी और बहुउद्देशीय कंपनियों के यूनिट आज गोरखपुर में लग रहे हैं।

शहरी और औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार

निवेश बढ़ने के साथ-साथ शहर का नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। नोएडा प्राधिकरण की तर्ज पर 1989 में 27135 एकड़ क्षेत्र में बसा 56 सेक्टरों में विभाजित गीड़ा आज इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। यहां पेप्सीको द्वारा 1071 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, इसके अलावा, अंबुजा सीमेंट, कोका-कोला, गैलेंट, अंकुर उद्योग, इंडिया ग्लाइकोल्स, केयान ग्रुप, ज्ञान डेयरी, कपिला कृषि उद्योग के अतिरिक्त टेराकोटा, फर्टिलाइजर प्लास्टिक गारमेंट पार्क की यूनिट काम कर रही है। गोरखपुर की सबसे

आधारभूत सुविधाओं के बढ़ने से बुनियादी सेवाओं विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा बदलाव इन दिनों देखने को मिल रहा है। खासकर एम्स के बन जाने से पूर्वांचल के लोगों के लिए लखनऊ पर निर्भरता कम हुई है। प्रतिदिन हज़ारो लोग सस्ता इलाज प्राप्त कर रहे है। शहर में कई सुपर स्पेशलियटी हॉस्पिटल खुले हैं।अस्पताल, लैब और इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ी हैं। अब गोरखपुर में ही सस्ता और अच्छा इलाज उपलब्ध है।

डॉ-अशोक यादव, वरिष्ठ शल्य चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर

बड़ी औद्योगिक परियोजना ग्रेटर गीड़ा के रूप में धुरियापार टाउनशिप है, जो लगभग 5500 एकड़ में एक हाईटेक टाउनशिप के रूप में प्रस्तावित है, जिसमें 10000 करोड़ का निवेश होगा जिससे 16 हजार रोजगार सृजित होंगे।

आधारभूत संरचना का विकास निर्माण एवं सुंदरीकरण

गोरखपुर के बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की है तो इसके साथ ही साथ सरकारी संस्थाएं, ठेकेदार, निजी बिल्डर हैं। वर्तमान में क्राफ्ट मायस्पेस, डीवीआर कंस्ट्रक्शन, इंटेज इंटरप्राइजेज, युग इंटीरियर जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। जो बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जिसकी लागत 5876 करोड़ है तो वहीं 4672 करोड़ की मेट्रो लाइट परियोजना है। इसके अलावा 3000 करोड़ का रिलायंस एफएमसीजी प्लांट है। जीडीए की 1680 फ्लैट की योजना और नई टाउनशिप गुरुकुल सिटी बन रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य 2027 तक गोरखपुर के बुनियादी ढांचे, यातायात व्यवस्था एवं पर्यटन क्षेत्र में बदलाव लाकर इसे देश के बेहतरीन शहरों की श्रेणी में शामिल करना है। हालांकि 22 नवंबर 2021 को ही गोरखपुर को महानगर का दर्जा प्राप्त हो चुका है और 2017 के बाद एक के बाद एक जो सौगातें मिल रही हैं उससे शहर की अलग ही तस्वीर नज़र आएगी।

अभी हाल ही में सोनबरसा में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट पंचायत भवन और बिछिया में कल्याण मंडपम का निर्माण करने वाली एच एस कंस्ट्रक्शन के युवा कांट्रेक्टर रितेश सिंह पूरे जोश और उत्साह से गोरखपुर में चल रहे विकास का ब्यौरा देते हैं। उनका कहना है कि -पिछले 50 वर्षों में जो सोचा नहीं होगा वैसा गोरखपुर बन रहा है। हर तबके को ध्यान में रखते हुए नवनिर्माण और सुंदरीकरण का गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है। जीडीए द्वारा 62 सरकारी विद्यालयों को और बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। बाहर से गोरखपुर आकर काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए न्यूनतम किराए पर -वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है *- रितेश सिंह, कांट्रेक्टर*

ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जिनमें कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ प्रक्रिया में है और कुछ प्रस्तावित है। इसमें दो राय नहीं कि जब यह योजनाएं आकार लेंगी तो उस दिन गोरखपुर दुनिया के नक्शे पर अपनी नई पहचान के साथ दिखाई देगा।

ओवर-ब्रिज, फ्लाई ओवर, अंडरपास का बड़ा नेटवर्क बनने एवं सड़कों का चौड़ीकरण और मरम्मत से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिली है। रामगढ़ ताल क्षेत्र, जो इससे पहले जलकुंभी, गंदगी, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के इकट्ठा होने की जगह के कारण सूर्यास्त के बाद एक निषिद्ध क्षेत्र बन चुका था, वह आज गोरखपुर के मरीन ड्राइव के नाम से जाना जा रहा है। लगभग ढाई हजार करोड़ की योजनाएं इसके इर्द-गिर्द ही चल रही हैं। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, लग्जरी क्रूज इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स कंपलेक्स और नजदीक में ही चिड़ियाघर, नक्षत्रशाला, प्रेक्षागृह, पार्क, बौद्ध संग्रहालय जैसे आकर्षक स्थल के साथ यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट है।

कमर्शियल डेवलपमेंट से गोरखपुर में टीयर 1 शहरों की तरह बड़े मॉल बन चुके हैं और अभी भी 5 से 10 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र वाले मॉल प्रस्तावित हैं, इनमें लुलु मॉल का भी प्रस्ताव है। इनमें अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के शोरूम मल्टीप्लेक्स थिएटर हैं। वर्तमान में गोरखपुर में लगभग 6 पांच सितारा होटल हैं। इसके अलावा ब्रांडेड कैफे खुल रहे हैं, जो शहर के रईस होने का एहसास दे रहे हैं। एक नगर निगम, आठ नगर पंचायत, 7

बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं पर जिस तीव्र गति से कार्य हो रहा है उससे गोरखपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के प्रति बाहर के लोगों का आकर्षण बढ़ा है। जो शहर नेपाल जाने वाले पर्यटकों के लिए रास्ते में पड़ने वाला एक विश्राम स्थल मात्र था, अब वही गोरखपुर एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में भारत के नक्शे पर नजर आ रहा है। एक मजबूत ढांचा, पर्यटकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन के लिए आकर्षक स्थल होने से यहां होटल व्यवसाय को गति मिली है। पहले जहां कुछ गिने चुने ही रेस्टोरेंट और होटल थे तो आज कोर्टयार्ड मैरियट, रेडिसन ब्लू, रामादा होटल अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जल्द ही आईटीसी, हालीडे इन, ताज होटल भी शहर में आने वाले हैं इससे यहां पहले से स्थापित होटल व्यवसायी भी प्रतिस्पर्धा करते हुए सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ उच्च स्तरीय सेवाएं दे रहे है, -अचिंत्य लहरी, होटल व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता

"शहर के बदलाव के लिए बड़े और कड़े कदम उठाये गए हैं। कुछ असुविधा हुई होगी जो स्वाभाविक है लेकिन जो बदलाव दिख रहे है वो मुग्ध करने के साथ-साथ आशान्वित करने वाले है। लोगों की मनः स्थिति को बदलाव के लिए तैयार करना और अपने अनुरूप बनाना बड़ी चुनौती थी। लेकिन जिस भाव विचार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यह कार्य हो रहा है वह अब दिखने लगा है। आज जब इतना सुंदर लग रहा है तो कुछ समय बाद जब सभी परियोजनाएँ पूरी हो जाएंगी तब क्या सुंदरता होगी इसकी कल्पना आप कर सकते हैं स मुझे तो बहुत उज्जवल भविष्य के साथ नया गोरखपुर नज़र आ रहा है और इसके लिए शासन, प्रशासन के साथ साथ गोरखपुर की विचारशील जनता को भी बधाई दी जानी चाहिए

- सुधा मोदी कवयित्री, सामाजिक कार्यकर्ता

गोरखपुर के विकास की उपलब्धियां

- सबसे महत्वपूर्ण और गोरखपुर के लिए वरदान 7 दिसंबर 2021 को लगभग 31 साल बाद फ़िर से शुरू हुआ गोरखपुर फ़र्टिलाइज़र कारखाना है, जो 8600 करोड़ की लागत से पूर्वांचल की सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें 10000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- बनारस के घाट की तरह राजघाट का सुंदरीकरण।
- पूर्वांचल के इतिहास, गौरव एवं आध्यात्मिकता को दर्शाता 25 करोड़ की लागत से बन रहा गोरखपुर गौरव म्यूजियम।
- 300 करोड़ की लागत से वेटरनरी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित।
- गीड़ा के सेक्टर 7 में राज्य सरकार द्वारा संचालित पहला होटल मैनेजमेंट कॉलेज 'स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट'।
- 750 बेड की क्षमता वाले 1500 करोड़ की लागत से गोरखपुर एम्स का निर्माण।
- मानीराम में उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स।
- लगभग 400 करोड़ की लागत से वूमेन पीएसी बटालियन प्रस्तावित।
- गोरखपुर उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां प्रतिदिन 16 से 18 उडानें अब भरी जा रही हैं। इसके नए टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव है, जिसमें 1000 करोड़ की लागत है।
- गोमती रीवर फ्रंट की तर्ज पर 550 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर लम्बा गोड़धोईया नाला प्रोजेक्ट जिसपर योगी जी का विशेष ज़ोर है।
- 550 करोड़ की लागत से धर्मशाला बाजार से पांडेयहाता तक 3.50 किमी लंबी है, विरासत गलियारा परियोजना।
- 49 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में उत्तर प्रदेश का पहला इकोलॉजिकल पार्क।
- गोरखपुर -सोनौली फोरलेन रोड जो 1455 करोड़ की लागत से तैयार होगा।
- 2100 बेड की क्षमता के साथ गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बेड वाला मेडिकल कॉलेज।
- राजघाट पुल 250 करोड़ की लागत के साथ आठ लेन का बनाया जा रहा है।
- लाल कांड़ला के पास एनसीसी एकैडमी का निर्माण।
- तारामंडल परिसर में पूर्वांचल का पहला साइंस पार्क, म्यूजियम और साथ ही 45 करोड़ की लागत से तारामंडल को अपग्रेड कर देश का सबसे हाईटेक तारामंडल बनाने का प्रस्ताव।
- गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर लाल कांडला के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है।
- 73 करोड़ की लागत से महेसरा ताल सुंदरीकरण परियोजना।

तहसील, 19 विकासखंड और 1354 ग्राम पंचायतों वाले गोरखपुर का हर क्षेत्र विकास की नई इबारत लिख रहा है और यह आने वाले कुछ वर्षों में अगले कई वर्षो के लिए इस क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखेगा।

कुछ लोग यह मानते हैं कि गोरखपुर में यदि कमी है, तो केवल मेट्रो जिसका प्रस्ताव पहले ही जा चुका है और दूसरी तरफ आईटी कंपनियों की। उम्मीद है जल्द ही इस कमी को भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का सपना गोरखपुर को लेकर काफी बड़ा है और इसके प्रति वे बेहद गंभीर है। इसका प्रभाव है कि विकास की बात आने पर योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी भी शहर में हो रहे विकास कार्यों की भूरी-भूरी प्रसंशा करते हैं। हक़ीक़त में शहर बदल रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। गोरखपुर प्रगति पथ पर नये दिनमान की ओर कदम बढ़ा चुका है...।■

"ष्गोरखपुर मेट्रो सिटी है आज यह सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों के अनुरूप ही आकार ले रहा है। आधारभूत संरचना के विकास ने साहित्यिक सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का रास्ता खोला है अब शहर बड़े आयोजनों के लिए तैयार हैस यहां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, भव्य गोरखपुर महोत्सव, संगीत कला और रंगमंच के बड़े आयोजन हो रहे हैं जिसमे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आ रहे हैं जो इस बदलाव को देख रहे हैं और सराह रहे हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि तो है

-नवीन श्रीवास्तव, उद्यमी, समाजसेवी

राजनीति

पंचायत वॉयस, नई दिल्ली

अप्रैल का चुनावी महायुद्ध

अप्रैल इस बार सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का एक निर्णायक पड़ाव भी है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी-देश के पांच अलग-अलग राजनीतिक स्वभाव वाले राज्य-एक साथ चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। यह सिर्फ सत्ता बदलने का मौका नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति, चुनावी रणनीति और मतदाताओं की सोच के बदलते स्वरूप को समझने का भी अवसर है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जब इन चुनावों की तारीखों की घोषणा की तो यह स्पष्ट था कि इस बार चुनाव सिर्फ समय पर कराने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि उसे अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने की कोशिश भी है।

इन चुनावों की सबसे बड़ी खासियत पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। जहां पहले चुनाव कई चरणों में लंबे समय तक चलते थे, वहीं इस बार मतदान को केवल दो चरणों-23 और 29 अप्रैल तक सीमित कर दिया गया है।

यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है। लंबे चुनाव अक्सर राजनीतिक वातावरण को ज्यादा आक्रामक और कटु बना देते हैं, जहां मुद्दों की जगह आरोप-प्रत्यारोप और भावनात्मक ध्रुवीकरण हावी हो जाता है। ऐसे में कम चरणों का यह निर्णय इस उम्मीद के साथ देखा जा रहा है कि चुनावी बहस ज्यादा सार्थक मुद्दों-विकास, रोजगार और शासन पर केंद्रित रहेगी।

इस बार चुनाव आयोग ने पूरे कार्यक्रम को अप्रैल महीने के भीतर केंद्रित रखा है। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल (पहला चरण) और 29 अप्रैल (दूसरा चरण) को मतदान होगा।

इसके अलावा विभिन्न राज्यों की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। गोवा की पोंडा, कर्नाटक की बागलकोट और दावणगेरे साउथ, नगालैंड की कोरिडांग और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि गुजरात की उमरेठ और महाराष्ट्र की राहुरी और बारामती सीट पर 23 अप्रैल को उपचुनाव कराए जाएंगे। सभी राज्यों और उपचुनावों के वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

इन चुनावों का असली आधार वे करोड़ों मतदाता हैं, जिनकी भागीदारी लोकतंत्र को अर्थ देती है। असम में कुल 2.4 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ पुरुष और 1.2 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं, साथ ही 343 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। यहां 126 सीटों पर चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में करीब 7 करोड़ मतदाता हैं-3.6 करोड़ पुरुष, 3.4 करोड़ महिला और 1402 थर्ड जेंडर मतदाता। यहां 294 सीटों पर मतदान होगा। तमिलनाडु में कुल 5.6 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 2.7 करोड़ पुरुष, 2.8 करोड़ महिला और 7617 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। यहां 234 सीटों पर चुनाव होगा। केरल में करीब 2.6 करोड़ मतदाता हैं-1.3 करोड़ पुरुष, 1.3 करोड़ महिला और 277 थर्ड जेंडर मतदाता। यहां 140 सीटों पर मतदान होगा। पुडुचेरी में लगभग 9.4 लाख मतदाता हैं, जिनमें 4.4 लाख पुरुष, लगभग 5 लाख महिला और 139 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। यहां 30 सीटों पर चुनाव होंगे। यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र की व्यापकता और समावेशिता का प्रमाण हैं।

इन चुनावों के पीछे एक स्पष्ट संवैधानिक कारण भी है-इन राज्यों की विधानसभाओं का समाप्त होता कार्यकाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु में यह 10 मई तक है। असम में यह अवधि 20 मई तक सीमित है। केरल में विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को खत्म हो रहा है। पुडुचेरी में यह 15 जून तक चलता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने पूरे कार्यक्रम को इस तरह संतुलित किया है कि नई सरकारें समय पर बन सकें और प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे।

- **पांच राज्यों की सियासत में बदलती रणनीति, सिमटते चरण और लोकतंत्र की नई दिशा**
- **वोटर तैयार, नेता मैदान में, अब फैसला जनता के हाथ में**
- **4 मई की गिनती नहीं, सत्ता का फैसला होगा उस दिन**

इन चुनावों को एक साथ देखना आसान है, लेकिन हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक धड़कन है। असम में चुनाव पहचान, विकास और क्षेत्रीय संतुलन के सवालों के इर्द-गिर्द घूमता है। पश्चिम बंगाल में यह अक्सर वैचारिक टकराव और सत्ता संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। तमिलनाडु में राजनीति संगठित और मजबूत दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का उदाहरण है। केरल में मुद्दा-आधारित राजनीति और वैचारिक स्पष्टता की परंपरा अब भी कायम है। पुडुचेरी में स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है।

इन चुनावों की असली कहानी आंकड़ों से ज्यादा मतदाताओं के बदलते व्यवहार में छिपी है। आज का मतदाता सिर्फ परंपरा या भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर ठोस जवाब चाहता है। युवाओं की बढ़ती भागीदारी और डिजिटल माध्यमों की पहुंच ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। अब चुनाव सिर्फ प्रचार का खेल नहीं, बल्कि धारणा और विश्वसनीयता की लड़ाई भी बन चुका है।

मुख्य चुनावों के साथ होने वाले उपचुनाव भले ही सीमित हों, लेकिन उनका राजनीतिक महत्व कम नहीं होता। ये अक्सर यह संकेत देते हैं कि जनता का मूड किस दिशा में जा रहा है और आने वाले समय में राजनीति किस दिशा में मुड़ सकती है।

जब 4 मई को नतीजे आएंगे, तब यह तय हो जाएगा कि इन पांच राज्यों में सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह होगा कि क्या इस चुनाव ने राजनीतिक संवाद की दिशा को थोड़ा बदलने में सफलता पाई है।

कम चरणों में चुनाव कराने का प्रयोग, विशाल मतदाता आधार और बदलती प्राथमिकताएं-ये सभी संकेत देते हैं कि भारतीय लोकतंत्र सिर्फ जीवित ही नहीं, बल्कि लगातार विकसित भी हो रहा है और शायद यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है।■

ममता का किला बनाम भाजपा का मिशन

- **दो चरण, एक लड़ाई और सत्ता की जंग**
- **30% अल्पसंख्यक और निर्णायक महिला मतदाता**
- **साइलेंट सपोर्ट और रणनीतिक वोटिंग तय कर सकते हैं सत्ता का समीकरण।**

पंचायत वॉयस, नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता की लड़ाई सिर्फ सीटों की गणित नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों, पहचान की राजनीति और जमीनी पकड़ की परीक्षा बन चुकी है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे-23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 4 मई को मतगणना के साथ यह तय हो जाएगा कि बंगाल की बागडोर किसके हाथ में जाएगी।

लेकिन इस चुनाव की असली कहानी तारीखों से कहीं आगे है। यह कहानी है एक ऐसे नेता की, जिसने पिछले डेढ़ दशक में बंगाल की राजनीति को अपने इर्द-गिर्द केंद्रित कर दिया है और एक ऐसी पार्टी की, जो हर हाल में उस किले को तोड़ना चाहती है।

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ताकत सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा राजनीतिक मॉडल बन चुकी है, जो सीधे जनता से जुड़ता है। पिछले चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के बाद ममता बनर्जी ने अपने शासन को योजनाओं और सामाजिक गठजोड़ के जरिए मजबूत किया है। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु वे वर्ग हैं, जो सीधे सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं-महिलाएं, ग्रामीण परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर तबका। यही वजह है कि सत्ता विरोधी माहौल की आशंकाओं के बावजूद ममता का आधार अब भी ठोस नजर आता है। भाजपा ने बंगाल को अपनी राष्ट्रीय राजनीति के विस्तार का सबसे अहम मैदान बना लिया है। पिछले चुनाव में मिली सफलता ने पार्टी को यह भरोसा दिया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन संभव है।

इस बार पार्टी पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है। अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, हिंदू पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर भाजपा चुनावी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है।

लेकिन असली चुनौती यह है कि क्या यह नैरेटिव जमीनी स्तर पर वोट में बदल पाएगा। बंगाल की राजनीति में भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का जो महत्व है, वहां सिर्फ मुद्दों की राजनीति हमेशा निर्णायक नहीं होती।

राज्य की लगभग एक तिहाई आबादी अल्पसंख्यक समुदाय से आती है, और यह वर्ग कई सीटों पर चुनावी परिणाम तय करता है। वाम दलों और कांग्रेस के कमजोर होने के बाद यह वोट बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। यह सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक झुकाव है, जो भाजपा के खिलाफ एकजुटता के रूप में सामने आता है। यही वह समीकरण है, जिसने पिछले चुनाव में तृणमूल को बढ़त दिलाई और इस बार भी यही भाजपा के सामने सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। जब तक इस समीकरण में दरार नहीं पड़ती, तब तक सत्ता की राह भाजपा के लिए मुश्किल बनी रहेगी।

भाजपा जहां पहचान की राजनीति के जरिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, वहीं ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक अंदाज में बदलाव करते हुए संतुलन की रणनीति अपनाई है। उन्होंने खुद को केवल एक वर्ग की नेता के रूप में सीमित नहीं रहने दिया। धार्मिक आयोजनों में भागीदारी, सांस्कृतिक प्रतीकों से जुड़ाव और क्षेत्रीय अस्मिता पर जोर-इन सभी के जरिए उन्होंने एक व्यापक छवि गढ़ी है। यही संतुलन भाजपा की रणनीति को चुनौती देता है, क्योंकि यह ध्रुवीकरण की संभावनाओं को सीमित कर देता है।

बंगाल में महिला मतदाताओं की भूमिका अब चुनावी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। ममता बनर्जी ने इस वर्ग को सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त करने की कोशिश की है। योजनाओं के जरिए सीधे लाभ पहुंचाकर उन्होंने एक स्थायी समर्थन तैयार किया है, जो चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भाजपा भी इस वर्ग को आकर्षित करने के लिए अपने वादों और अभियानों पर जोर दे रही है, लेकिन जमीन पर प्रभावी पकड़ बनाना आसान नहीं है। यह वही वर्ग है, जो अक्सर खुलकर राजनीतिक रुझान नहीं दिखाता, लेकिन मतदान के दिन परिणाम बदलने की क्षमता रखता है।

तृणमूल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक हमला भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर है। भाजपा इन मुद्दों को लगातार उभार रही है और इसे सरकार के खिलाफ असंतोष में बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उसकी योजनाओं और जमीनी काम ने जनता के बीच भरोसा कायम किया है। यह चुनाव काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा कि मतदाता आरोपों को ज्यादा महत्व देता है या अपने जीवन में हुए बदलाव को।

हर चुनाव में कुछ ऐसे कारक होते हैं, जो अंतिम नतीजों को अप्रत्याशित बना देते हैं। बंगाल में भी यह पूरी तरह संभव है। अगर भाजपा अपने समर्थन को शहरी इलाकों से निकालकर ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला पाती है और नए मतदाताओं को जोड़ने में सफल होती है तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस अपने पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने में सफल रहती है तो सत्ता में वापसी की राह उसके लिए आसान हो सकती है।

पश्चिम बंगाल का चुनाव 2026 अब सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि दो राजनीतिक दृष्टिकोणों की सीधी टक्कर बन चुका है। एक ओर ममता बनर्जी हैं, जिनका वर्चस्व अब भी राज्य की राजनीति पर स्पष्ट दिखता है। दूसरी ओर भाजपा है, जो हर हाल में इस वर्चस्व को चुनौती देना चाहती है। मतदान की तारीखें तय हो चुकी हैं, मैदान सज चुका है और रणनीतियां खुलकर सामने आ रही हैं। अब नजर 4 मई पर टिकी है-जब यह तय होगा कि बंगाल की सत्ता एक बार फिर ममता के हाथ में जाती है या भाजपा इतिहास रचने में सफल होती है। बंगाल की जनता ही इस कहानी का अंतिम अध्याय लिखेगी।■

सियासत

राज्यसभा में NDA का 'सुपर स्ट्राइक', विपक्ष क्यों हुआ ध्वस्त?

सत्ता के गलियारों में बदला संतुलन, 22 सीटों की ताकत से बदला खेल, 15 पर सिमटा विपक्ष, अब किसकी चलेगी?

पंचायत वॉयस, नई दिल्ली

भारतीय राजनीति में कई बार चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि वे उस गहरे बदलाव का संकेत होते हैं, जो आने वाले समय की सत्ता और नीति निर्माण को प्रभावित करता है। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर हुए हालिया चुनावों ने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। यह चुनाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि संसद के ऊपरी सदन में बदलते शक्ति संतुलन की कहानी है, जहां एनडीए ने अपनी स्थिति मजबूत की है और विपक्ष को स्पष्ट झटका लगा।

37 सीटों में से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। असली मुकाबला तीन राज्यों की 11 सीटों पर हुआ, जहां वोटिंग के बाद आए नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदल दी। अंतिम आंकड़ों में एनडीए ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष 15 सीटों पर सिमट गया। यह अंतर केवल संख्या का नहीं, बल्कि प्रभाव का भी है।

इस चुनाव में एनडीए की सफलता का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि यह जीत केवल एक पार्टी की नहीं थी, बल्कि पूरे गठबंधन की समन्वित रणनीति का परिणाम थी। बीजेपी ने 13 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन इसके साथ ही उसके सहयोगियों ने भी अहम भूमिका निभाई।

जेडीयू ने अपनी दोनों सीटें सुरक्षित रखीं। शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, पीएमके, एआईएडीएमके, यूपीपीएल और आरएलएसएम जैसे सहयोगी दलों ने एक-एक सीट जीतकर गठबंधन को मजबूती दी। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी एनडीए के समर्थन से जीतकर आया।

यह संकेत साफ है कि एनडीए अब केवल राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी गहरी जड़ें जमा चुका है। राज्यसभा जैसे सदन में यह विस्तार उसे विधायी बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित हो सकता है। विपक्ष के लिए यह चुनाव मिश्रित परिणाम लेकर आया। कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं, जो उसके लिए आंशिक राहत की बात है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपनी 4 सीटें बरकरार रखीं, जिससे उसकी क्षेत्रीय पकड़ कायम दिखी। डीएमके को हालांकि एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा और वह 3 सीटों पर आ गई। शरद पवार की एनसीपी को एक सीट मिली, जबकि बीजेडी भी एक सीट ही जीत सकी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ज्यादा गंभीर है। आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), सीपीआईएम और बीआरएस जैसे दलों को बड़ा नुकसान हुआ। कुछ दल तो पूरी तरह शून्य पर पहुंच गए। यह स्थिति विपक्ष के लिए केवल चुनावी हार नहीं, बल्कि रणनीतिक कमजोरी का संकेत है।

अगर चुनाव से पहले और बाद की स्थिति की तुलना की जाए तो असली बदलाव समझ में आता है। एनडीए के पास पहले 12 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 22 हो गई हैं। यानी उसे 10 सीटों का सीधा फायदा हुआ है। इसके उलट विपक्ष के पास पहले 25 सीटें थीं, जो अब घटकर 15 रह गईं। यानी उसे भी 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा।

यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में संख्या का सीधा असर कानून बनाने की प्रक्रिया पर पड़ता है। अब सरकार के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा।

इस चुनाव की असली कहानी राज्यों के भीतर छिपी है, जहां स्थानीय राजनीति ने राष्ट्रीय परिणाम तय किए...

महाराष्ट्र में 7 सीटों पर हुए मुकाबले में बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर बढ़त बनाई। एनसीपी और शिवसेना को एक-एक सीट मिली, जबकि एक सीट पर शरद पवार की जीत हुई। यहां बीजेपी को दो सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार गुट को नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर, अजित पवार और शिंदे गुट को लाभ मिला।

तमिलनाडु में 6 सीटों के चुनाव में डीएमके को एक सीट का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को एक सीट का लाभ मिला। एआईएडीएमके और पीएमके ने अपनी सीटें बचाए रखीं। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों में टीएमसी ने अपनी 4 सीटें बरकरार रखीं, जबकि बीजेपी को एक सीट का फायदा हुआ। लेफ्ट को यहां नुकसान झेलना पड़ा।

बिहार की 5 सीटों में जेडीयू ने अपनी दोनों सीटें सुरक्षित रखीं। आरजेडी को 2 सीटों का नुकसान

हुआ, जबकि बीजेपी को 2 सीटों का फायदा मिला। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी सीट बरकरार रखी।

ओडिशा में 4 सीटों पर बीजेपी ने अपनी दोनों सीटें बचाए रखीं और एक निर्दलीय को समर्थन देकर जीत दिलाई। बीजेडी को एक सीट का नुकसान हुआ।

असम की 3 सीटों में बीजेपी ने अपनी दोनों सीटें सुरक्षित रखीं, जबकि असम गण परिषद को नुकसान हुआ।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक सीट का फायदा हुआ और कांग्रेस को एक सीट गंवानी पड़ी।

तेलंगाना की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत लीं, जिससे उसे लाभ मिला और बीआरएस को नुकसान हुआ।

हरियाणा में दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती, लेकिन बीजेपी को एक सीट का नुकसान हुआ।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक सीट का फायदा मिला, जबकि बीजेपी को नुकसान हुआ।

इन चुनावों ने एक बार फिर यह दिखाया कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अब भी अहम है। लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि केवल क्षेत्रीय ताकत होना काफी नहीं है-सही समय पर सही गठबंधन बनाना भी जरूरी है।

जो दल गठबंधन राजनीति के साथ तालमेल बैठा पाए, उन्होंने अपनी स्थिति बचाए रखी या मजबूत की। वहीं जो दल अलग-थलग रहे, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।

राज्यसभा में बढ़त का सीधा असर केंद्र सरकार की कार्यशैली पर पड़ेगा। अब सरकार के लिए

विधेयकों को पास कराना अपेक्षाकृत आसान होगा। खासकर वे बिल, जो पहले अटक जाते थे, अब तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। विपक्ष के लिए यह समय आत्ममंथन का है। उसे अपने गठबंधन, नेतृत्व और रणनीति पर नए सिरे से काम करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो आने वाले चुनावों में यह अंतर और बढ़ सकता है।

राज्यसभा चुनाव 2026 ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय राजनीति में संतुलन तेजी से बदल रहा है। एनडीए की बढ़त केवल वर्तमान की जीत नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक बढ़त भी है।

वहीं विपक्ष के लिए यह परिणाम एक चेतावनी है-अगर उसने समय रहते अपनी दिशा नहीं बदली, तो उच्च सदन में उसकी भूमिका और सीमित हो सकती है।

इस चुनाव ने एक बार फिर साबित किया है कि लोकतंत्र में हर सीट मायने रखती है, और हर चुनाव भविष्य की राजनीति की दिशा तय करता है। इस बार की दिशा स्पष्ट है-सत्ता पक्ष की पकड़ मजबूत हो रही है और विपक्ष को नई रणनीति की जरूरत है।■

जम्मू-कश्मीर

....अब बदला-बदला नजर आ रहा जम्मू-कश्मीर

राज लक्ष्मी

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे बही विकास की बयार, इसकी बानगी चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है. जम्मू-कश्मीर अब बदला-बदला नजर आ रहा है। न सिर्फ सियासी तौर पर, बल्कि आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी। घाटी में अलगाववादियों के आह्वान पर अघोषित कर्फ्यू (जनजीवन प्रभावित होना) बीते जमाने की बात हो गई। आज हालात यह है कि अब घाटी में रेल परिचालन तक शुरू हो गया है, जिसका कभी विरोध किया जाता था। अब पर्यटक वंदे भारत जैसे ट्रेन में बैठकर घाटी पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, विस्टाडोन जैसी रेलगाड़ी में बैठकर घाटी के मनमोहक दृश्य का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की इच्छाशक्ति का जिक्र करना नहीं भूलते हैं।

केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में 5 अगस्त 2019 को अचानक जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने की घोषणा की, जिसका स्थानीय सियासी दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) व नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तक किए। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अब कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन आज हालात यह है कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने न सिर्फ अपनी लोकप्रिय सरकार का चयन किया, बल्कि केंद्र सरकार ने पंचायत से लेकर त्रिस्तरीय चुनाव करवाकर अपने फैसले को सही भी साबित कर दिया।

नतीजा, अनुच्छेद 370 का विरोध करने वाले सियासी दल हासिए पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनावों में 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ। वर्ष 2020 में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव हुए और 2024 में विधानसभा चुनावों में भी युवाओं और महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकार जरुर घट गए। वर्तमान में नेशनल कान्फ्रेंस (एनसी) की सरकार सत्ता पर काबिज है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, पुलिस और सेवाओं पर नियंत्रण उपराज्यपाल को दे दिया गया। इससे निर्वाचित सरकार के अधिकार सीमित हो गए। हालांकि, गाहे-बगाहे जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठते रहती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल का पहला फैसला भी राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया था। इन सबके बीच आज न सिर्फ जम्मू-कश्मीर देश के अन्य राज्यों के साथ तेजी से विकास की रफ्तार में शामिल है, बल्कि वर्ष 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ। जम्मू संभाग में कठुआ जैसे पिछड़े क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रोजगार के अवसर बढ़ाए गए। साथ ही देश-विदेश के बड़े औद्योगिक घराने को भी आमंत्रित किया गया।

अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो जम्मू में आइआइटी और रियासी में मेडिकल कालेज शुरू हुआ। इतना ही नहीं, जम्मू संभाग में विजयपुर व कश्मीर संभाग में अवंतीपोरा में एम्स का निर्माण किया गया। दूरदराज के इलाकों से छात्र यूपीएससी जैसी परीक्षाएं पास कर रहे हैं। सरकार की ओर से जाब फेयर और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी देखी जा रही है।

जम्मू-कश्मीर में 6 साल में करीब 90 हजार करोड़ का निवेश हुआ, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे बही विकास की बयार, इसकी बानगी चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, जहां पहाड़ को चीरते हुए हाईवे तक का विस्तार किया जा रहा है। अगले पांच माह में छह मार्गीय दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस-वे के शुरू हो जाने की उम्मीद है। हालांकि, आधे से ज्यादा हिस्से पर निर्माण कार्य पूरा भी हो गया है।

बालीवुड को रास आ रही कश्मीर की वादियां

22 अप्रैल 2025 को अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास बैसरन घाटी में हुए आतंकी

"जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के बाद से शांति, निवेश और पर्यटकों में इजाफा हुआ है। 'जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का विकास इस समय हो रहा है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था अब बनी है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है। जन कल्याण की योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिलने लगा है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में पर्यटन को पंख लग गए हैं।"

- राजीव जसरोटिया, विधायक, जसरोटा एवं पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता

हमले से कुछ समय के लिए पर्यटन उद्योग को जरुर झटका लगा, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा भी आतंकी घटना का विरोध किए जाने व राज्य व केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के कारण दोबारा पर्यटन उद्योग पटरी पर लौटते नजर आ रही है। अब न सिर्फ कश्मीर घाटी में ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि जम्मू संभाग के कठुआ जिले के सरथल जैसे पर्यटन स्थल पर विटंर फेस्टिवल करवाकर पर्यटन को जम्मू क्षेत्र भी पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। कठुआ के बनी के अलावा कश्मीर के दूर दराज के गांवों में बालीवुड फिल्मों की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई है। इनमें कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के नागरानार गांव में "परेशान" नाम की हारर फिल्म की शूटिंग हुई। यह पहली बार है कि कोई फिल्म निर्माण इकाई इस दूरस्थ गांव में शूटिंग के लिए पहुंची है, इससे सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। नियंत्रण रेखा के निकट स्थित कुपवाड़ा जिले में पहली बार किसी फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग ने साबित किया कि किस तरह जम्मू-कश्मीर आज बदला-बदला नजर आ रहा है। इस दौरान शूट पर मौजूद क्रू सदस्यों ने बताया कि उन्हें यह स्थान शांत और शूटिंग के लिए उपयुक्त लगा। नागरानार का प्राकृतिक परिवेश और शांत वातावरण हारर फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि, क्रू ने यह खुलासा नहीं किया कि परियोजना के लिए स्थान का चयन कैसे किया गया।

इतना ही नहीं, बालीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भी घाटी के बर्फ से ढके इलाकों में अपनी आगामी अनाम खेल ड्रामा फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा किया। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहलगाम में भी हुई। अभिनेता ने पहलगाम के बर्फीले इलाकों में कई अहम दृश्यों की शूटिंग की। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कबीर खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म बांडीपोरा जिले के युवा किक बाक्सिंग प्रतिभा तजामुल इस्लाम के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित है। तजामुल ने बेहद कम उम्र में वैश्विक ख्याति प्राप्त की और विश्व के सबसे कम उम्र के किकबाक्सिंग चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। मात्र सात साल की उम्र में सब-जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली वह पहली कश्मीरी

बनीं। कार्तिक कथित तौर पर ताजामूल के कोच की भूमिका निभा रहे हैं।

घाटी में खुला पहला मल्टीप्लेक्स

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात कितने सामान्य हुए, इसका जीता जागता तस्वीर दो वर्ष पहले कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खुलना है, जहां आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। साथ ही लगभग तीन दशक के बाद घाटी के लोगों ने पहली बार सिनेमा हाल में फिल्म भी देखा। हालांकि, कभी कश्मीर सिनेमा शूटिंग की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन दो दशक तक सिर्फ पत्थरबाजी ही होते रही। बताया जाता है कि पत्थरबाजी की घटना जो हर हर साल लगभग 2000 हजार तक होती थी, लेकिन अब न के बराबर है। गत वर्ष यानि 34 साल बाद मुहर्रम के जुलूस निकलने की अनुमति मिली तो पिछले साल 75 साल बाद दीवाली मनाई गई। कश्मीर पंडित लगातार नवरेह मना रहे हैं।

पर्यटकों के आमद में इजाफा

अब तक लगभग दो करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में आ चुके हैं। इनमें लगभग 45 हजार विदेशी हैं। पहली बार शारजाह के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हुई। एक सरकार आंकड़े के अनुसार 35 हजार युवाओं को अनुच्छेद-370 हटने के बाद सरकारी नौकरी दी गई। 2018 में केवल 9,229 प्रोजेक्ट हर साल पूरे होते थे, लेकिन आज तेजी से सभी प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं। छह साल में लगभग 70 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए।

अब श्री अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने की तैयारी

अब राज्य प्रशासन श्री अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार बैठकें हो रही है। माना जा रहा है कि माह के अंत तक श्री अमरनाथ यात्रा और एडवांस पंजीकरण शुरू करने की तिथि की घोषणा हो सकती है। यह तय है कि एडवांस पंजीकरण अप्रैल से शुरू हो जाएगा और पहलगाम व बालटाल के दोनों यात्रा मार्गों पर बर्फ हटाने का कार्य मई में आरंभ होगा। जम्मू-कश्मीर के साल 2026-27 के बजट में सरकार ने यात्रा प्रबंधों के लिए 180 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इससे यात्रा के दोनों मार्गों के विस्तार, मरम्मत, संवदेनशील जगहों पर रेलिंग लगाने, यात्री निवास में सुविधाओं में बढ़ोतरी के कार्य किए जाएंगे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की कोशिश है कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं।■

साक्षात्कार

सेहत की बात... पूर्वांचल के वरिष्ठ और अनुभवी फिजीशियन डॉक्टर त्रिलोक रंजन जी से खास बातचीत...

बढ़ते तापमान के साथ रखें स्वास्थ्य का ध्यान

सौम्या द्विवेदी

मौसमी बीमारी की चपेट में आने से इंसान की दिनचर्या बिगड़ जाती है और असहज होकर उल्टी-सीधी दवाओं का सेवन कर लेता है, एक बीमारी ठीक नहीं होती कि दूसरी जन्म लेती हैं। इससे हमारे सामने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतयां खड़ी हो जाती हैं...इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कि बदलते मौसम में कैसे स्वस्थ्य रहे, क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे सामंजस्य बैठाएं। इन तमाम सवालों को लेकर "पंचायत वॉयस" ने अपने प्रवेशांक अंक में पाठकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से अपडेट करने के लिए पूर्वांचल के वरिष्ठ और अनुभवी फिजीशियन डॉक्टर त्रिलोक रंजन जी एक खास मुलाकात की, हमारे पाठक इससे लाभान्वित हों। आइए जानते हैं सौम्या द्विवेदी के साथ हुई इस खास बातचीत "सेहत की बात" अंश...

सावल : *सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में खासकर अब जब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं कौन-सी हैं और हम स्वस्थ रहने के लिए किस तरह सामंजस्य बनाएं..?*

जवाब : किसी भी मौसम में तापमान का बदलाव हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, क्यूंकि हमारे शरीर का तापमान निश्चित है। गर्मियों में तापमान बढ़ने से पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से तरल पदार्थ का लगातार ह्रास होता है। इसमें केवल पानी ही नहीं निकलता, बल्कि उसके साथ इलेक्ट्रो लाइट्स, खनिज भी चला जाता है। इसलिए जो चीज़ शरीर से बाहर हो रही है, उसकी आपूर्ति भी होती रहे इसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात तापमान बढ़ने से ऐसे पैथोजेन्स, वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा भी निकलते हैं, जिनके विकास के लिए तापमान अनुकूल होने पर उनकी वृद्धि ज्यादा होने की सम्भावना बढ़ जाती है, जिससे उनके द्वारा होने वाली बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। तीसरी बात ये कि नियमित उपयोग में आने वाली जो चीजें है, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ वो जल्दी खराब होने लगते हैं। इसमें पैथोजेन्स की वृद्धि होने से खाद्य पदार्थो से होने वाली बीमारियां बढ़ेंगी। अगर इन सामान्य बातों का ध्यान रखा जाए और कुछ सतर्कता बरतें तो तापमान के बदलाव के साथ एक सामंजस्य बनाया जा सकता है।

सवाल : *एक समस्या डिहाइड्रेशन की जो बड़ों और बच्चों दोनों में दिखती है। इसके शुरुआती संकेत क्या हैं, और अगर ये समस्या है तो उसके घरेलू उपचार क्या हैं और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए...?*

जवाब : देखिये शरीर के लिए आवश्यक पानी की मात्रा से कम पानी होना ही डिहाइड्रेशन है। गर्मियों में यदि हम आवश्यकता से कम पानी का उपयोग करते हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके शुरुआती संकेत यह है की मरीज को बहुत तेज प्यास लगती है, दूसरा जीभ लगातार सूखने लगती है और सबसे अधिक गंभीर संकेत जिसे सामान्य व्यक्ति भी पहचान सकता है, वो ये कि उसकी पेशाब की आवृत्ति कम हो जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब करता है। अगर ये कम हो रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन के संकेत है। ऐसे में ओआरएस घोल या नींबू-चीनी-पानी का घोल प्रयोग करें, यदि आराम नहीं मिलता तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें।

सवाल : *लू लगने पर घरेलू उपाय क्या हो सकता है और डॉक्टर को कब दिखाना ज़रूरी है...?*

जवाब : यदि लू लगने पर मरीज को प्यास लगे या जीभ सूखने तक की समस्या है तो घर पर उसको ओआरएस और पानी दिया जाए, लेकिन अगर पेशाब की आवृत्ति कम हो रही है तो बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए घरेलू इलाज को छोड़कर ऐसे किसी भी व्यक्ति या मरीज को तत्काल चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, ताकि उसका समुचित इलाज हो सके।

सवाल : *गर्मी में स्किन-रैशेज, सनबर्न, फंगल इन्फेक्शन की समस्या गंभीर रूप ले लेती है, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए...?*

जवाब : ये महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रैवलर या जो लोग बाहर काम करते हैं, विशेष रूप से महिलाएं, इसके अलावा मज़दूर, डिलीवरी स्टाफ इनके लिए ये समस्या है।

इन समस्याओं में घर पर किसी भी तरह का प्रयोग या उपचार करने से बचें और तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें।

सवाल : *जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो ख़ुद अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो उनके माता-पिता क्या कुछ खास करना चाहिए...?*

जवाब : बच्चों के स्कूल बैग के साथ पानी की बोतल जरूर रखें। बोतल नियमित साफ हो, उन्हें घर का बना ताज़ा खाना साफ बर्तन में दिया जाना चाहिए और प्रयास हो कि बाहर का खाना विशेष रूप से खुले स्थान पर मिलने वाले ठेले दुकानों पर मिलने वाली चीजों को खाने से रोकना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर में पानी जरूर पिलाते रहें भले प्यास लगे या ना लगे।

सवाल : आजकल यूथ और सीनियर लोगों में भी वर्कआउट का एक क्रेज दिखता है। क्या गर्मी के मौसम में कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए...?

जवाब : हालांकी अब जिम समान्यता एसी युक्त होते हैं मगर फ़िर भी यदि पसीना ज्यादा होता है तो अवश्यकतानुसार व्यायाम करना चाहिए। साथ में एनर्जी ड्रिंक्स लें और पानी का सेवन खूब करें।

सवाल : *जो मरीज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी समस्याओ से ग्रसित हैं उनके लिए कुछ सलाह...?*

जवाब : ऐसे मरीजों के लिए जरूरी है कि अपने डॉक्टर से परामर्श करके जो भी निर्देश मिले उन्हें पालन करें, ताकि तापमान के बढ़ने से कोई अन्य समस्या ना हो।

सवाल : *अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों में हमें कैसा रूटीन follow करना चाहिए...?*

जवाब : सामान्य दिनचर्या ही अपनाएं। प्रयास करें कि सुबह जल्दी उठ कर ताजा वायु में प्राणायाम, व्यायाम करें। ■

सिस्टम की खामियां

"रागिनी मैम, आपको नहीं लगता कि हमें विद्यालय के चारों ओर एक चारदीवारी बनवा देनी चाहिए। आसपास की गायें, कुत्ते और दूसरे जानवर बार-बार विद्यालय के अंदर आ जाते हैं । सभी लोग इस समस्या से परेशान हो चुके हैं।" शालिनी ने विद्यालय के प्राचार्य कक्ष में बैठी रागिनी गोयल से कहा। रागिनी कुछ देर मौन रही फिर शांतिपूर्वक बोली, "देखिए शालिनी जी। हम आपकी समस्या समझते हैं पर चारदीवारी बनाने के लिए तो छोड़ो विद्यालय की मरम्मत करवाने तक के लिए भी हमारे पास पैसों की कमी है।

"तो आपको पंचायत का रुख करना चाहिए। "शालिनी ने झटपट जवाब दिया। रागिनी निराश होकर बोली, "राज्य सरकार से नियमित समय पर धनराशि न मिलने के कारण ग्राम के सभी निर्माणधीन कार्य स्थगित कर दिए गए है। हमारे पास कहीं से भी पैसों की व्यवस्था करने का कोई साधन नहीं है।"

"पंचायत को राज्य सरकार से आवेदन करना चाहिए। "कुछ देर सोचते हुए शालिनी बोली। "आवेदन करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। विद्यालय के अलावा बरगद के पेड़ के पास जिस हास्पिटल का निर्माण हो रहा था, वह भी रुक गया है। इसके अलावा बहुत सी सरकारी योजनाएँ भी अधर में लटकी हुई हैं।" रागिनी बोली। उनकी बातें सुनने के बाद पास खड़ा चपरासी बोला, "मैडम जी, ये सिस्टम की खामियां देखकर तो लग रहा देश का सिस्टम ही देश का भविष्य बिगाड़ रहा है।"

आराध्या नयाल, कक्षा-6
रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल, विकास नगर, सेक्टर-14, लखनऊ

कार्यालय जिला पंचायत, देवरिया

'पंचायत वॉयस' पत्रिका के शुभारम्भ पर हार्दिक शुभकामनाएं

अपील

जिला पंचायत देवरिया के समस्त बकायेदारों से अनुरोध है कि जिला पंचायत के समस्त देयक को जमा कर विकास के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करें।

पत्रांक-837/ जि०पं०/ देवरिया

अखिलेश्वर मल्ल
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, देवरिया

गिरीश तिवारी
अध्यक्ष
जिला पंचायत, देवरिया

P डॉ.अंजना सिंह सेंगर

तुम्हीं को गीत अर्पित है

तुम्हीं को गीत अर्पित है, तुम्हीं को प्रीत अर्पित है,
करूं वंदन नमन तुमको, तुम्हें श्रद्धा समर्पित है।

सुशोभित नौ स्वरूपों में, शरद वासंत में आए,
सजे हर गेह तेरा दर, दिलों में भी सुसज्जित है।

हरे दुख-दर्द, पीड़ा को, सदा मंगल करे माता,
तुम्हारे प्यार की महिमा, पुराणों में सुवर्णित है।

करे संहार दुष्टों का, मनुजता का करे पालन,
तुम्हारी शक्ति से माता, विनिर्मित सृष्टि पोषित है।

करूं सब कुछ समर्पित मैं, करो स्वीकार पूजा को,
शरण में लो जगत जननी, मुझे तो मोक्ष इच्छित है।

जो मैया को मन से ध्याए

नवरातन त्योहार बरस में, आता है दो बार,
अपने भक्तों से मिलने माँ आती हैं साकार।

शंख, पुष्प अरु चक्र धारिणी, हाथ भाल, तलवार,
लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, रहती सिंह सवार।

माता की महिमा इस जग में, देखो अपरंपार,
जो मैया को मन से ध्याए, उसका बेड़ा पार।

कातर स्वर में भक्त पुकारें, आओ माता द्वार,
लोभ मोह के नश्वर जग से, हमको को दो अब तार।

तुम ही जग की जननी हो माँ, करती हो उपकार,
कहे 'अंजना'कर दो मैया, सबका तुम उद्धार।

विज्ञापन

RNI : UPHIN/26/A0322

पंचायत वॉयस

पंचायत से परिवर्तन...

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

यह पत्रिका देश के ग्रामीण और शहरी जीवन में व्याप्त चुनौतियों के निराकरण एवं बेहतरी की संभावनाओं पर आधारित जन सरोकार से जुड़ी है। हमारा मूलभूत उद्देश्य "पंचायत से परिवर्तन" का है, जहां गांव की पंचायत से लेकर देश की पंचायत तक की बात होगी। हमारा जोर समाज में पत्रकारिता को मजबूती के साथ खड़ा करने पर है। हमारी कोशिश है कि हिन्दी पत्रकारिता में "तथ्य ही सत्य है" का मूल्य स्थापित हो।

आवश्यकता है:-

पंचायत वॉयस मासिक पत्रिका के लिए ब्यूरो चीफ, नगर संवाददाता एवं विज्ञापन प्रतिनिधि हेतु देश के सभी शहरों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं आप हमारे पते पर संपर्क करें।

दूरभाष: 9876917688

कार्यालय 39/166, नियर यूनिटी सिटी, कल्याणपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226022

panchayatvoice.up@gmail.com www.panchayatvoice.in

Panchayat Voice

आर्थिक सहयोग

जनसरोकार से जुड़ी पत्रकारिता के लिए आप हमारा सम्बल बनें, 'पंचायत वॉयस' को करें सहयोग

Account Details
A/c Name : Panchayat Voice
A/c No. : 031402000011565
Bank Name : IDBI Bank
IFSC : IBKL0000314
Branch : Manoj Pandey Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow (UP)-226010

IDBI BANK

कार्यालय नगर पालिका परिषद सुलतानपुर

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

"स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता"

नगर वासियों से नगर पालिका परिषद सुलतानपुर की विनम्र अपील

1- नगर क्षेत्र में यातायात में जाम की समस्या न हो, इसके लिए अपने आवास एवं दुकानों के सामने मार्गों की पटरियों पर दुकान की सामग्री न लगायेंगे तथा किसी भी पथ विक्रेता को ठेला, गुमटी इत्यादि न खड़ा होने दें, उन्हें वेन्डिंग जोन में ही पथ विक्रय कार्य करने हेतु प्रेरित करें।

2- प्रतिबन्धित पॉलीथीन एवं थर्माकोल के उत्पादों का उपयोग दण्डनीय है, एकल उपयोग की प्लास्टिक का प्रयोग कदापि न करें।

3- नगर में नाले नालियों से अवैध अतिक्रमण स्वयं हटा लें, ताकि नालियों की सफाई में असुविधा न हो।

4- घरो एवं दुकानों से दैनिक निकलने वाले कूड़े को रोड व नाली में न फेकें बल्कि समय से पालिका के कूड़ा गाड़ी वाहन के पहुंचने पर गीला एवं सूखा कूडा वाहन में अलग-अलग डाले।

5- डेंगू एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचाव हेतु अपने कूलर, घर की छत अथवा परिसर में तथा आस-पास कहीं पर भी पानी जमा न होने दें, न ही कूड़ा करकट, गन्दगी इत्यादि ही इकट्ठा होने दें, बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें।

6- घरों के सेप्टिक टैंक प्रत्येक तीन वर्ष के अन्दर सुरक्षित तरीके से अवश्य साफ करायें, सेप्टिक टैंक का स्लज नाले अथवा खुले स्थान पर कदापि न डालें, तत्सम्बन्धी किसी समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर-14420 पर अवश्य सम्पर्क करें।

7- हाथ से मैला ढोना अथवा ढोने के लिए प्रेरित करना निषिद्ध है, ऐसा कदापि न करें एवं न ही करायें। यदि ऐसा होता पाया जाय, तो पालिका को सूचित करें।

8- खुले में शौच अथवा पेशाब न करें, शौचालय एवं पेशाबघर का प्रयोग प्रयोग करें।

9- अपने शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 में अपने फीडबैक द्वारा शहर को नम्बर-01 बनायें।

10- जल ही जीवन है, अतः इसे बर्बाद होने से बचायें।

11- पालिका की सेवाओं से सम्बन्धित किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए टोल फ्री नम्बर 1533 पर शिकायत दर्ज करायें।

नगर पालिका परिषद सुलतानपुर
"सुन्दर स्वच्छ सुलतानपुर"
बनाने हेतु सदैव संकल्पित

लाल चन्द्र सरोज
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सुलतानपुर

समस्त सभासदगण
नगर पालिका परिषद,
सुलतानपुर

प्रवीन कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
सुलतानपुर

पत्रांक: 179/न०पा०परि०सुल०/2025-26

हक़ीक़त परत दर परत

सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस

सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी

निर्माणाधीन कॉलेज

संचालित द्वारा- पं० मनबोध चौबे एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट

भारत सरकार और यू०जी०सी० अप्रूव्ड युनिवर्सिटी से डिग्री/डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स (B.VOC) करें।

डिप्लोमा	एडवांस डिप्लोमा	डिग्री
1 साल	2 साल	3 साल

- लैब टेक्नीशियन
- ओ.टी. टेक्नीशियन
- आप्टोमेट्री टेक्नीशियन
- डायलिसिस टेक्नीशियन
- रेडियोलॉजी एण्ड मेडिकल इजेजिंग
- कार्डिक केयर टेक्नीशियन
- हॉस्पिटल स्टेलाइजेशन
- पेशेंट केयर मैनेजमेंट
- हॉस्पिटल मैनेजमेंट
- डायटिक्स एण्ड न्यूट्रीशन
- बी.पी.टी.- बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी
- एनेस्थिसीया
- फार्मेसी असीस्टेंट
- अर्ली चाइल्ड केयर एण्ड एजुकेशन
- रुरल हेल्थ एण्ड सैनीटेशन
- बी-फार्मा*/डी-फार्मा*

प्रवेश प्रारम्भ, 2026-27

SC/ST/OBC
छात्रों के लिए स्कालरशीप
40% तक की छूट

9336548360, 9120008360

पता- ग्रा० कुलडोमरी (मेडरदह) निकट- अनपरा-ओबरा रोड, जिला-सोनभद्र
प्रशासनिक ब्लाक- डिबुलगंज (अनपरा) वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग-सोनभद्र
ब्रांच- सांईनाथ हॉलिस्टिक हॉस्पिटल, हिंदुआरी, राबर्ट्सगंज- सोनभद्र

डिप्लोमा/ डिग्री कोर्सेस सभी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी हेतु मान्य

Email- sardarvpatelcollegepharmacy@gmail.com ★ https://svbpcsonbhadra.org/

आलोक पांडेय मिंटू - प्रबंधक, अनपरा सोनभद्र, मो. 7398064538

DP MOTORS, Near MMM Engineering college, Deoria Road, Gorakhpur, Mob. 7081802001/02